website: www.royalpatrika.com
G-mail: royalpatrika@gmail.com
Yahoo: royal_patrika@yahoo.com

R.N.I. No. RAJHIN/2012/48736

दैनिक

रॉयल पत्रिका

वर्ष : 14 | अंक : 63 | पेज: 8 | जयपुर, गुरुवार 12 फरवरी 2026 | मूल्य: 1.50 रुपये

पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने कहा कि मूल्यों पर आधारित पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत और विचार देश की हर पीढ़ी

के लिए पथ-प्रदर्शक बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मातृभूमि के अनन्य उपासक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। मूल्यों पर आधारित उनके सिद्धांत और विचार देश की हर पीढ़ी के लिए पथ-प्रदर्शक बने रहेंगे।" एक अन्य पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, "सर्वस्व समर्पण उस चेतना की अभिव्यक्ति है, जिसमें राष्ट्र और मानवता सर्वोपरि होती है। अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी इसी भावना से देश के जन-जन को सशक्त बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।" इसके साथ ही, प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाषित भी शेयर किया है। उन्होंने संस्कृति श्लोक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा, "यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः। यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम॥" इस संस्कृति सुभाषित का अर्थ है, "जिस राष्ट्र की महिमा का गान हिमालय करता है, जिसकी कीर्ति नदियों के साथ समुद्र तक प्रवाहित होती है और जिसकी भुजाओं के समान दिशाएं उसे नमन करती हैं, उस राष्ट्र को हम अपना सर्वस्व समर्पित करें।"

कनाडा के स्कूल में गोलीबारी: हमलावर समेत 10 की मौत

नई दिल्ली (एजेंसी)। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में टंबलर रिज स्थित एक हाई स्कूल में मंगलवार को सामूहिक गोलीबारी हुई, जिसमें हमलावर समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस

(आरसीएमपी) ने बताया कि हाई स्कूल के अंदर छह लोग मृत पाए गए, जबकि एक अन्य व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। संदिग्ध हमलावर भी मृत पाया गया, जिसकी मौत खुद को पहुंचाई गई चोट के कारण हुई। स्थानीय मीडिया के अनुसार, घटना से जुड़े एक घर में भी दो लोगों के शव मिले हैं। पुलिस का मानना है कि इस घर का संबंध गोलीबारी की घटना से है। घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमएलए लैरी न्यूफेल्ड ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि वे टंबलर रिज की स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। उन्होंने फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स, स्कूल स्टाफ और स्थानीय अधिकारियों की तेज़ और पेशेवर प्रतिक्रिया की सराहना की। उन्होंने छात्रों, परिवारों, शिक्षकों और पूरे समुदाय के लिए अपनी दुआएं भी भेजीं। न्यूफेल्ड ने लोगों से अपील की कि वे पुलिस को जांच पूरी करने और विवरण की पुष्टि करने का समय दें। उन्होंने कहा कि यदि किसी को मानसिक या भावनात्मक कठिनाई हो रही है, तो वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। पुलिस ने फिलहाल संदिग्ध के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है और गोलीबारी के कारणों की जांच जारी है।

देश में 29,151 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित : केंद्र

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि देश में अब तक कुल 29,151 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) स्थापित किए जा चुके हैं। भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना बिना लाइसेंस वाली

गतिविधि घोषित किया गया है। निजी संस्थाओं को विद्युत मंत्रालय के 17 सितंबर 2024 के दिशानिर्देशों के अनुसार ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने की अनुमति दी गई है। सरकार ने सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना को मजबूत करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकास को बढ़ावा देने के लिए एफएएमई-II और पीएम ई-ड्राइव योजनाओं के तहत विभिन्न कदम उठाए हैं। टियर-2 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एफएएमई-II योजना के तहत 912.50 करोड़ रुपये और पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। एफएएमई-II योजना में आवंटित 912.50 करोड़ रुपये में से 633.44 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 26 सितंबर 2025 को ईवीपीसीएस विकास के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देश पात्र सार्वजनिक और निजी संस्थाओं को चार्जिंग अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन का ढांचा प्रदान करते हैं। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भरोसेमंद और व्यापक चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गति देना है। सरकार की यह योजना देश में ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और हरित परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

योगी सरकार का विकास बजट:

सड़क, सिंचाई, एमएसएमई और आईटी सेक्टर पर बड़ा निवेश

यूपी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में अवस्थापना, औद्योगिक विकास, एमएसएमई, आईटी, सड़क, सिंचाई और ग्रामोद्योग क्षेत्रों के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए हैं। बजट में पूंजीगत निवेश के जरिए रोजगार सृजन और औद्योगिक विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है।

अवस्थापना और औद्योगिक विकास को मजबूती:-

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 2,000 करोड़ रुपए तथा एफडीआई और फॉर्च्यून-500 कंपनियों को प्रोत्साहन नीति के क्रियान्वयन के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में 35,280 करोड़ रुपए के संभावित निवेश के साथ 200 एमओयू हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं, जिससे 53,263 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

एमएसएमई और युवा उद्यमिता पर फोकस:-

एमएसएमई क्षेत्र के लिए 3,822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से 19% अधिक है। 'सरदार वल्लभभाई पटेल इम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन' योजना के लिए 575 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हेतु 1,000 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। 'एक जनपद एक व्यंजन' योजना के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

हथकरघा, वस्त्रोद्योग और टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा:-

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र के लिए 5,041 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया

है, जो पिछले वर्ष की तुलना में पांच गुना से अधिक है। पावरलूम बुनकरों के लिए 4,423 करोड़ रुपए की फ्लैट रेट विद्युत योजना तथा वस्त्र एवं गारमेंटिंग नीति-2022 के लिए 150 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। पीएम मित्र पार्क योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में निवेश और रोजगार को गति मिलने की उम्मीद है।

आईटी, एआई और डेटा सेंटर पर विशेष ध्यान:-

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 2,059 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो 76% अधिक है। उत्तर प्रदेश एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपए तथा साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र के लिए 95 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से आठ डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने और 900 मेगावॉट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

सड़क, सेतु और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा:-

सड़क एवं सेतु निर्माण के लिए 34,468 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर, बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर और औद्योगिक लॉजिस्टिक मार्गों के विकास के लिए अलग-अलग मदों में हजारों करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए 18,290 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो 30% अधिक है। केन-बेतवा लिंक सहित प्रमुख परियोजनाओं से 4.49 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होने का अनुमान है। 2,100 नए राजकीय नलकूपों और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से लाखों किसानों तथा करीब 49.90 लाख आबादी को लाभ मिलने का दावा किया गया है।

लोकसभा स्पीकर के चैंबर में घुसकर अभद्रता की गई और भला-बुरा कहा गया : किरेन रिजिजू

नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ अभद्र व्यवहार किया। किरेन रिजिजू ने बताया कि जब यह घटना हुई, वह भी मौके पर मौजूद थे।

विपक्ष सदन के अंदर स्पीकर के निर्देशों का खुलेआम करता है उल्लंघन

उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन के अंदर स्पीकर के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन करता है और फिर उन पर उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाता है। केंद्रीय मंत्री ने पार्लियामेंट के नियमों को बार-बार तोड़ने के लिए विपक्ष की भी आलोचना की और उन्हें स्पीकर के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन पेश करते समय भी तय नियमों और नॉर्म्स को मानने की सलाह दी।

लोकसभा स्पीकर की बातों को नहीं माना

संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, "लोकसभा स्पीकर के चैंबर में घुसकर अभद्रता की गई और भला-बुरा कहा गया। फिर, स्पीकर ने जो रूलिंग दिया। उसे भी नहीं माना। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें सदन में बोलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। वे अपनी मर्जी से बोलेंगे। यह मेरा बोलने का अधिकार है। सब कुछ रिकॉर्ड पर है।" उन्होंने कहा कि जब तक सदन में स्पीकर से परमिशन नहीं मिलती है, तब तक कोई नहीं बोल सकता है। सदन का कोई भी सदस्य, चाहे वह सांसद हो या प्रधानमंत्री, स्पीकर की परमिशन से ही बोलता है, लेकिन विपक्ष के नेता के लिए पार्लियामेंट के नियमों का कोई मतलब नहीं है।

20-25 कांग्रेस सांसद लोकसभा स्पीकर के चैंबर में घुस गए और उनके साथ अभद्रता की

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आगे बताया कि कम से कम 20-25 कांग्रेस सांसद लोकसभा स्पीकर के चैंबर में घुस गए और उनके साथ अभद्रता की। मैं भी वहीं पर मौजूद था। स्पीकर बहुत नरम इंसान हैं, नहीं तो कड़े कदम उठा सकते थे। जिस वक्त स्पीकर के साथ अभद्रता की जा रही थी, उस समय केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई सीनियर नेता भी अंदर मौजूद थे, और वे उन्हें लड़ने के लिए उकसा रहे थे।

दिल्ली में सुनेत्रा पवार ने की पीएम मोदी और अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात

मुंबई। महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। उपमुख्यमंत्री पद संभालने के बाद यह उनका पहला आधिकारिक दिल्ली दौरा माना जा रहा है। इस मुलाकात को राजनीतिक और प्रशासनिक लिहाज से अहम बताया जा रहा है। इस दौरान उनके दोनों बेटे और एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। सुनेत्रा पवार ने इस भेंट की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा कीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को सौजन्य भेंट बताते हुए लिखा कि देश के नेतृत्व से मार्गदर्शन प्राप्त करना उनके लिए सम्मान की बात है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भी उन्होंने एक पोस्ट साझा कर आभार जताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में जो खालीपन आया है, उसे भरना आसान नहीं है, लेकिन उनके जनकल्याण और विकास के विजन को आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है। शाह ने भरोसा जताया कि सुनेत्रा पवार इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। गौरतलब है कि सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 10 फरवरी को मंत्रालय पहुंचकर आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाला। उन्हें खेल एवं युवा कल्याण, उत्पाद शुल्क और अल्पसंख्यक मामलों जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य के विकास, किसानों, महिलाओं, युवाओं और आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने इसे विश्वास, कर्तव्य और सेवा का अवसर बताया।

अनुराग ठाकुर का दावा: केंद्रीय बजट विकसित भारत के सपने को देगा नई रफ्तार

नई दिल्ली। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में केंद्रीय बजट को सरकार के 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट "सबका जिक्र, सबकी फिक्र" की भावना पर आधारित है और देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उनके अनुसार यह बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक विकास दृष्टि का रोडमैप है। अनुराग ठाकुर ने बजट को देश की प्रगति और समृद्धि को गति देने वाली "डेवलपमेंट एक्सप्रेस" करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक मजबूती, सामाजिक कल्याण और तकनीकी प्रगति को साथ लेकर चलने की नीति अपनाई है, जिससे विकास की रफ्तार और तेज होगी। यह बजट भविष्य की जरूरतों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार बजट में संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण दिखाई देता है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को मजबूती देने के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। गांवों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, किसानों को सहयोग देने, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और डिजिटल इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और युवाओं के कौशल विकास को उन्होंने समावेशी विकास के प्रमुख स्तंभ बताया। उनके मुताबिक इन क्षेत्रों में बढ़ाया गया निवेश समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर देगा और मानव संसाधन को मजबूत बनाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए ठाकुर ने कहा कि सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और शहरी ढांचे में बढ़ा निवेश बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा और बाजार में मांग को बढ़ाएगा। साथ ही हरित ऊर्जा, सतत विकास और तकनीकी आधुनिकीकरण को भी प्राथमिकता दी गई है, ताकि भारत वैश्विक मानकों के अनुरूप आगे बढ़ सके। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में विकास और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन रखा गया है। राजकोषीय समेकन, लक्षित सहायता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग से दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी। उनके अनुसार यह बजट "ए से जेड" तक हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम है।

'अच्छे दिन की उम्मीदों पर पानी फिर गया...', योगी सरकार के बजट पर मायावती की आई प्रतिक्रिया

यूपी। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार, 11 फरवरी को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 12.2 प्रतिशत ज्यादा बताया जा रहा है। बजट पेश होने के तुरंत बाद इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगीं। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की सुप्रीमो और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इस बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया वर्ष 2026-27 का बजट लोक लुभावना ज्यादा और जनता के वास्तविक उत्थान व प्रदेश में सर्वसमाज तथा सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिहाज से कम प्रभावी प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि बजट में की गई घोषणाओं और आश्वासनों के जरिए जनता को आकर्षित करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन जमीनी असर ज्यादा साफ नजर नहीं आता। उन्होंने आगे कहा कि अगर पिछले साल के बजट के वास्तविक क्रियान्वयन का सही और पारदर्शी डाटा भी बजट भाषण में शामिल किया जाता, तो यह परंपरा को ज्यादा ठोस और विश्वसनीय बनाता। उनके अनुसार मौजूदा बजट भी अखबारों की सुर्खियां बटोरने वाला ज्यादा लगता है, जिससे आम लोगों की 'अच्छे दिन' की उम्मीदों पर फिर से पानी फिरता दिखाई दे रहा है। बसपा प्रमुख ने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता अभी भी स्थायी आमदनी देने वाली रोजगार व्यवस्था का इंतजार कर रही है और इस दिशा में सरकार को ज्यादा गंभीरता और सक्रियता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि बैकलॉग भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार भी बीएसपी की सरकारों की तरह 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' की संवैधानिक भावना को ईमानदारी और निष्ठा से लागू करे तो यह प्रदेश और देश दोनों के जनहित में होगा। उनके मुताबिक बजट ऐसा होना चाहिए जो किसी खास वर्ग या क्षेत्र तक सीमित न रहे, बल्कि सभी वर्गों के लिए लाभकारी हो और खासकर करोड़ों गरीबों और किसानों के जीवन स्तर को सुधारने का माध्यम बने, न कि उनके हितों के खिलाफ जाए।

नई वैश्विक व्यवस्था की ओर भारत-ईयू व्यापार समझौता, रिपोर्ट में उभरी रणनीतिक तस्वीर

नई दिल्ली। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए), जिसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है, बदलती दुनिया की नई व्यवस्था की झलक दिखाता है। द गार्डियन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जब दुनिया में क्षेत्रीय सीमाओं पर खतरे, ऊंचे टैरिफ (कर) और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की कमजोरी बढ़ रही है, ऐसे समय में यह समझौता एक नई दिशा दिखाता है। यह व्यापार समझौता हाल ही में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया। इस समझौते से लगभग 2 अरब उपभोक्ता और दुनिया की कुल जीडीपी के करीब एक-चौथाई हिस्से को एक साथ लाने का वादा किया गया है। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय की एशियाई अध्ययन की प्रोफेसर रविंदर कौर लिखती हैं कि भारत-ईयू की बढ़ती साझेदारी यह दिखाती है कि दोनों पक्ष अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने, सुरक्षा और रक्षा, शोध, लोगों की आवाजाही और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भी ज्यादा भागीदारी शामिल है। वह आगे लिखती हैं कि जैसे-जैसे अमेरिका अपने

क्षेत्र तक सीमित होता दिख रहा है, हिंद-प्रशांत क्षेत्र यूरोपीय संघ के साथ सहयोग के लिए और अधिक खुल रहा है। उनका कहना है कि 'अमेरिका के बाद की दुनिया (पोस्ट-यूएस वर्ल्ड)' पहले से ही आकार ले रही है और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इसका एक उदाहरण है। ब्रसेल्स ने हाल ही में दक्षिण अमेरिका के मर्कोसुर ट्रेड ब्लॉक के साथ भी एक व्यापार समझौता किया है और ऐसे कई अन्य समझौते पाइपलाइन में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने पिछले कुछ महीनों में ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के साथ भी व्यापार समझौते किए हैं। कौर लिखती हैं कि भले ही इन समझौतों को लागू होने और पूरी तरह से प्रभावी बनने में समय लगे और बीच में कुछ अड़चनें भी आ सकती हैं, लेकिन यह साफ संकेत देता है कि वैश्विक स्तर पर बड़ा बदलाव हो रहा है। उनका कहना है कि दुनिया अब उस दिशा में बढ़ रही है, जिसका सपना लंबे समय से पश्चिम से बाहर के कई देश देखते रहे हैं- जैसे बहुध्रुवीय व्यवस्था, रणनीतिक स्वायत्तता और डॉलर पर निर्भरता कम करना। यह बदलाव पहले धीरे-धीरे और अब तेजी से आकार ले रहा है। वहीं, न्यूयॉर्क स्थित एशिया सोसाइटी के एक दक्षिण एशिया विशेषज्ञ का मानना है कि पिछले महीने भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ने संभवतः अमेरिका को भारत के साथ ट्रेड डील आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया होगा। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट (एएसपीआई) में दक्षिण एशिया पहल की निदेशक फरवा आमेर ने कहा, "भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता काफी समय से चल रही थी, लेकिन ईयू के साथ हुए समझौते ने अमेरिका को बातचीत तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि इस डील का समय काफी दिलचस्प है, क्योंकि यह ईयू-एफटीए के तुरंत बाद सामने आई है।

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई

मुंबई। मुंबई एयरपोर्ट कस्टम्स ने 4 जनवरी से 11 फरवरी 2026 के बीच कई छापों में ड्रग्स, सोना, हीरे और विदेशी मुद्रा की बड़ी जब्ती की। बैंकॉक से आए 7 यात्रियों से 13.256 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (करीब ₹13.25 करोड़) बरामद हुई। अलग मामलों में 104 ग्राम सोना, 246.75 कैरेट हीरे और लगभग ₹69.78 लाख की विदेशी करेंसी भी पकड़ी गई। सभी आरोपियों को NDPS एक्ट व अन्य धाराओं में गिरफ्तार कर जांच जारी है।

रॉयल पत्रिका

संपादकीय....

राजस्थान बजट 2026: राहत, विकास और चुनावी संतुलन का दस्तावेज

राजस्थान सरकार द्वारा पेश किया गया ताज़ा बजट कई मायनों में संतुलन साधने की कोशिश नजर आता है। एक ओर जहां आमजन को राहत देने की घोषणाएं की गई हैं, वहीं दूसरी ओर आधारभूत ढांचे, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का दावा किया गया है। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं और राजनीतिक संदेश का भी प्रतिबिंब है। सबसे पहले बात करें आम आदमी की। महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती जीवन-यापन लागत के बीच सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिए राहत देने का प्रयास किया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महिला सशक्तिकरण योजनाएं, किसानों के लिए अनुदान और युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम—ये सभी वर्गों को साधने की कोशिश दिखाई देती है। हालांकि, इन घोषणाओं की वास्तविक सफलता उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में विशेष प्रावधान स्वागतयोग्य हैं। सिंचाई परियोजनाओं, फसल बीमा और कृषि ऋण राहत की घोषणाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकती हैं। राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में यह आवश्यक भी है। लेकिन पिछली योजनाओं के अधूरे क्रियान्वयन को देखते हुए इस बार पारदर्शिता और निगरानी तंत्र मजबूत करना जरूरी होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विस्तार की बात की गई है। नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और चिकित्सा सुविधाओं की घोषणाएं सकारात्मक संकेत देती हैं। यदि इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया तो यह राज्य के मानव संसाधन विकास में बड़ा कदम साबित हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर—सड़क, बिजली, पानी और शहरी विकास—पर जोर देना राज्य की आर्थिक गति को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। निवेश आकर्षित करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में कुछ कदम उठाए गए हैं। लेकिन राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि बढ़ते व्यय और सीमित संसाधनों के बीच संतुलन साधना आसान नहीं है। कुल मिलाकर, यह बजट उम्मीदों और वादों से भरा हुआ है। अब असली परीक्षा सरकार की नीयत और प्रशासनिक क्षमता की होगी। घोषणाएं तभी सार्थक होंगी जब वे धरातल पर उतरेंगी। जनता को राहत, युवाओं को रोजगार और किसानों को स्थिर आय—यदि ये लक्ष्य हासिल होते हैं, तो यह बजट राज्य के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। राजस्थान की जनता अब केवल घोषणाएं नहीं, परिणाम चाहती है। यही इस बजट की असली कसौटी होगी।

विनोद सोखल
पत्रकार
श्रीगंगानगर
राजस्थान

बांग्लादेश चुनाव परिणाम और भारत की पूर्वी रणनीति, सुरक्षा, सीमा स्थिरता और कूटनीतिक संतुलन की बड़ी परीक्षा इस बार सामने

-नई सरकार का रुख तय करेगा भारत-बांग्लादेश रिश्तों और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा आगे कैसे

बांग्लादेश में होने जा रहे आम चुनाव केवल ढाका की सत्ता का सवाल नहीं हैं, बल्कि दक्षिण एशिया की पूरी रणनीतिक तस्वीर को प्रभावित करने वाली घटना हैं। भारत के लिए तो यह और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि हमारे सबसे लंबे स्थलीय सीमा संबंध इसी देश से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम — इन सभी राज्यों की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन, व्यापार और राजनीतिक माहौल पर बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति का सीधा असर पड़ता है। ऐसे में बांग्लादेश के चुनावों के नतीजे हमारे लिए सिर्फ कूटनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित का विषय हैं। इस बार का चुनाव कई वजहों से अलग है। अवामी लीग को चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई है, जिससे चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिर भी कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह सैन्य हस्तक्षेप के बिना हो रही है, जो बांग्लादेश के लोकतांत्रिक सफर में एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। सेना ने खुलकर किसी दल का समर्थन नहीं किया है और न ही चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यह स्थिति पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है, जहां अक्सर सेना की भूमिका चुनावी राजनीति पर भारी पड़ती रही है। भारत के लिए चिंता का मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि यह भी है कि नई सरकार किस तरह की विदेश नीति अपनाएगी — खासकर भारत के प्रति उसका रुख कैसा होगा।

भारत-बांग्लादेश संबंध: टकराव से सहयोग तक का सफर

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों ने पिछले डेढ़ दशक में एक लंबा सफर तय किया है। कभी सीमा विवाद, अवैध आव्रजन, सीमा पार अपराध और जल बंटवारे के मुद्दों से घिरे ये संबंध धीरे-धीरे सहयोग और भरोसे की दिशा में आगे बढ़े। यूपीए-2 सरकार के दौरान भूमि सीमा समझौते की नींव पड़ी, जिसे बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अंतिम रूप दिया गया। 6 जून 2015 को भूमि सीमा समझौते को मंजूरी मिलना एक ऐतिहासिक कदम था। इससे दशकों पुराने एन्क्लेव (छिटपुट बस्तियों) का मसला सुलझा। हजारों लोग जो कानूनी पहचान से वंचित थे, उन्हें नागरिकता और प्रशासनिक सुविधा मिली। यह सिर्फ एक कूटनीतिक दस्तावेज नहीं था, बल्कि इंसानी गरिमा से जुड़ा फैसला था। इस समझौते के लिए केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, असम और त्रिपुरा के स्थानीय हितों और राजनीतिक विरोध — सबको साथ लेकर चलना पड़ा। यह दिखाता है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, तो जटिल सीमाई विवाद भी सुलझाए जा सकते हैं। आज बांग्लादेश भारत का वह एकमात्र बड़ा पड़ोसी है, जिसके साथ हमारे सभी प्रमुख सीमा विवाद औपचारिक रूप से सुलझ चुके हैं। यह उपलब्धि छोटी नहीं है।

चुनाव और विश्वसनीयता का सवाल

इस बार के चुनाव में अवामी लीग की अनुपस्थिति से विपक्षी दलों — खासकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) — को बढ़त मिलती दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिना सबसे बड़े दल की भागीदारी के चुनाव पूरी तरह प्रतिनिधिक कहे जा सकते हैं? लोकतंत्र का असली मतलब केवल वोटिंग नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक भागीदारी है। अगर बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला दल चुनाव से बाहर है, तो परिणाम चाहे जो हों, उन पर बहस होगी। फिर भी, यह भी सही है कि बांग्लादेश लंबे समय से राजनीतिक ध्रुवीकरण और सड़क आंदोलन की राजनीति से जूझता रहा है। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया का जारी रहना भी एक तरह की संस्थागत मजबूती का संकेत है। भारत को इस स्थिति को भावनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक नजरिए से देखना होगा।

क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ रहा है?

भारत में अक्सर यह आशंका जताई जाती है कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो बांग्लादेश कट्टरपंथ की ओर बढ़ सकता है। लेकिन उपलब्ध जनमत सर्वेक्षण कुछ अलग कहानी बताते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, व्यापार का खराब माहौल — ये वहां के लोगों के असली मुद्दे हैं। इस्लामीकरण या भारत-विरोधी राष्ट्रवाद चुनावी एजेंडे का मुख्य विषय नहीं है। बीएनपी और जमात — दोनों ने अपने चुनाव अभियानों में पाकिस्तान का नाम लगभग नहीं लिया है। जमात ने भी भारत के साथ सामान्य और सम्मानजनक संबंधों की बात की है। बीएनपी भी आपसी सम्मान पर आधारित रिश्ते चाहती है। यह संकेत बताता है कि बांग्लादेशी समाज में कट्टर विचारधाराओं की स्वीकार्यता सीमित है। अगर सर्वेक्षणों पर भरोसा करें तो जमात को प्रधानमंत्री पद के लिए सीमित समर्थन मिल रहा है, जबकि मुख्य मुकाबला बीएनपी के नेतृत्व के इर्द-गिर्द है। इसका मतलब यह है कि वहां की जनता वैचारिक टकराव से ज्यादा आर्थिक स्थिरता चाहती है।

अंतरिम सरकार और विदेश नीति के संकेत

मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पिछले डेढ़ साल में कुछ ऐसे कदम उठाए, जिन्हें भारत में शंका की नजर से देखा गया। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को बुलाना, रक्षा सौदों की बात करना, उत्तर-पूर्व भारत को लेकर बयान देना — ये सब कदम अनावश्यक रूप से उकसाने वाले माने गए। शेख हसीना को भारत में शरण दिए जाने पर आपत्ति जताना भी कूटनीतिक संतुलन के लिहाज से कठोर प्रतिक्रिया थी। लेकिन यह भी समझना होगा कि अंतरिम सरकारें अक्सर घरेलू दबाव और वैधता के संकट से जूझती हैं। वे कई बार प्रतीकात्मक कदम उठाकर घरेलू समर्थन जुटाने की कोशिश करती हैं। भारत को इन कदमों को स्थायी नीति मानकर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि अंतरिम व्यवस्था ज्यादा लंबी नहीं चलेगी और चुनी हुई सरकार जल्द सत्ता संभालेगी। इससे नीति में स्थिरता आने की उम्मीद है।

भारत की कूटनीतिक चाल: संकेत और संतुलन

भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के एक प्रमुख नेता के अंतिम संस्कार में विदेश मंत्री को भेजकर एक व्यावहारिक संदेश दिया — कि नई राजनीतिक वास्तविकताओं से संवाद के दरवाजे खुले हैं। विपक्षी नेतृत्व से मुलाकात भी इसी दिशा का संकेत है। कूटनीति में रिश्ते सरकारों से होते हैं, दलों से नहीं। भारत को यह सिद्धांत याद रखना होगा। अगर नई सरकार बीएनपी की बनती है, तो उससे कामकाजी रिश्ता बनाना ही समझदारी होगी।

पूर्वी भारत की राजनीति और बांग्लादेश

बांग्लादेश का मुद्दा भारत की घरेलू राजनीति से भी जुड़ जाता है — खासकर पश्चिम बंगाल और असम में। "घुसपैठ" और "अवैध प्रवासी" जैसे नारे चुनावी भाषणों में अक्सर गूंजते हैं। इससे सीमा पार रिश्तों पर भी असर पड़ता है। अगर बांग्लादेश में चुनाव भारत के इन राज्यों के चुनावों के बाद होते, तो शायद बयानबाजी और तेज होती। लेकिन अभी केंद्र सरकार के पास मौका है कि वह राजनीतिक तापमान को नियंत्रित रखे और संतुलित भाषा का इस्तेमाल करे। विदेश नीति और चुनावी राजनीति का मिश्रण अक्सर दीर्घकालिक नुकसान करता है। पड़ोसी देशों को चुनावी मुद्दा बनाना अल्पकालिक लाभ दे सकता है, लेकिन रणनीतिक भरोसा कमजोर करता है।

"बांग्ला-भाषी पाकिस्तान" वाली आशंका क्या है?

जब यह कहा जाता है कि "हमें एक बांग्ला-भाषी पाकिस्तान नहीं चाहिए", तो उसका मतलब यह है कि भारत अपने पूर्व में एक अस्थिर, भारत-विरोधी और सैन्य-प्रभावित राज्य नहीं चाहता। पाकिस्तान का अनुभव दिखाता है कि जब नागरिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और पहचान की राजनीति हावी होती है, तो क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती है। लेकिन बांग्लादेश की सामाजिक संरचना, भाषा आंदोलन का इतिहास, और आर्थिक प्रगति का मॉडल पाकिस्तान से अलग है। वहां नागरिक समाज अपेक्षाकृत मजबूत है, महिला भागीदारी अधिक है, और आर्थिक संकेतक बेहतर रहे हैं। इसलिए सीधी तुलना सही नहीं, पर चेतावनी के तौर पर चिंता समझी जा सकती है। भारत का लक्ष्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि स्थिरता को मजबूत करना होना चाहिए।

आर्थिक और रणनीतिक महत्व

बांग्लादेश आज दक्षिण एशिया की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में रहा है। वस्त्र उद्योग, निर्यात, श्रम शक्ति और सामाजिक सूचकांकों में उसने उल्लेखनीय सुधार किया।

बेमानी जंगों के मुहाने पर दुनिया, सत्ता, वर्चस्व और हथियारों की होड़ में घिरती मनुष्यता का बढ़ता खतरा आज स्पष्ट

-संघर्ष, राष्ट्रवाद और वैश्विक राजनीति के बीच शांति की संभावनाएं क्यों कमजोर पड़ रही हैं

कवि श्रीकांत वर्मा की कविता 'युद्ध नायक' की पंक्तियां आज फिर से भयावह सच्चाई की तरह हमारे सामने खड़ी दिखाई देती हैं—एक युद्ध से निकलकर दूसरे की ओर बढ़ती मनुष्यता, जैसे नींद में चलता हुआ कोई व्यक्ति। इतिहास की राख अभी ठंडी भी नहीं होती कि नए संघर्षों की चिंगारियां हवा पकड़ लेती हैं। ढाका, वियतनाम, यूरोप—ये केवल जगहों के नाम नहीं, बल्कि वे ज़ख्म हैं जिनसे होकर बीसवीं सदी गुज़री। अगर आज उन नामों को गाजा, यूक्रेन, इराक, अफगानिस्तान, ईरान या ताइवान से बदल दें, तो तस्वीर चौंकाने वाली समानता के साथ सामने आती है। सवाल यह है कि क्या हम सचमुच कुछ सीख पाए हैं या बस युद्ध के नए संस्करण बना रहे हैं? आज का दौर तकनीक, तरक्की और ग्लोबल कनेक्टिविटी का दौर कहा जाता है। लेकिन इसी दौर में युद्ध और टकराव की संख्या भी बढ़ी है। रूस-यूक्रेन संघर्ष, इजराइल-हमास युद्ध, मध्य-पूर्व की अस्थिरता, भारत-पाकिस्तान तनाव, आर्मेनिया-अजरबैजान संघर्ष, अमेरिका-ईरान टकराव—ये सब बताते हैं कि दुनिया शांति के रास्ते पर नहीं, बल्कि अविश्वास और शक्ति प्रदर्शन की राह पर बढ़ रही है। बड़ी ताकतें अपने-अपने दायरे मजबूत करने में लगी हैं और छोटे देश शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। दो विश्वयुद्धों ने मिलकर लगभग दस करोड़ लोगों की जान ली थी। वह दौर हथियारों की दृष्टि से आज की तुलना में बेहद सीमित था। आज परमाणु हथियारों, जैविक तकनीक, साइबर युद्ध और अंतरिक्ष सैन्यीकरण के इस युग में अगर कोई व्यापक युद्ध छिड़ता है तो उसके नतीजे कल्पना से परे होंगे। आइंस्टाइन से जुड़ा वह मशहूर कथन बार-बार याद आता है—"तीसरा विश्वयुद्ध जिन भी हथियारों से लड़ा जाएगा, चौथा पत्थरों से लड़ा जाएगा।" यह केवल मज़ाक नहीं, बल्कि सभ्यता के विनाश की चेतावनी है। तो आखिर यह नौबत बार-बार क्यों आती है? क्या इंसान की फितरत में ही टकराव छिपा है, या यह सत्ता, संसाधन और स्वार्थ की राजनीति का खेल है? एक बड़ा कारण है—राजनीतिक वर्चस्व की भूख। आधुनिक युद्ध अक्सर सीधे-सीधे ज़मीन या सीमाओं के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव क्षेत्र, संसाधन नियंत्रण, सामरिक बढ़त और वैश्विक दबदबे के लिए लड़े जाते हैं। तेल, गैस, पानी, खनिज—ये सब बहाने बनते हैं, असल मकसद ताकत का संतुलन अपने पक्ष में झुकाना होता है। कभी कहा जाता था अगला युद्ध पेट्रोल के लिए होगा, फिर कहा गया पानी के लिए होगा। अब लगता है कि युद्ध किसी भी बहाने से हो सकता है—नैरेटिव बस बदल दिया जाता है। दूसरा कारण है—राष्ट्रवाद का उग्र रूप। देशभक्ति एक सकारात्मक भावना है, लेकिन जब वही राष्ट्रवाद उन्माद में बदल जाता है, तब वह तर्क और मानवता को पीछे छोड़ देता है। सत्ता में बैठे लोग अक्सर जनता की भावनाओं को भड़काकर समर्थन जुटाते हैं। बाहरी दुश्मन का डर दिखाकर अंदरूनी नाकामियों से ध्यान हटाया जाता है। इतिहास गवाह है कि जब-जब सत्ता संकट में होती है, युद्ध का शोर तेज़ किया जाता है। तीसरा पहलू है—सैन्य-औद्योगिक ढांचा। हथियार उद्योग दुनिया के सबसे बड़े कारोबारों में से एक है। युद्ध जितने बढ़ेंगे, हथियारों की मांग उतनी बढ़ेगी। कई अर्थव्यवस्थाएं रक्षा सौदों और सैन्य तकनीक पर टिकी हैं। ऐसे में शांति हमेशा फायदे का सौदा नहीं मानी जाती। यह कड़वा सच है कि युद्ध कुछ लोगों के लिए कारोबार है, भले ही वह करोड़ों लोगों के लिए तबाही हो।

चौथा कारण—लोकतंत्र की कमजोरी और नेतृत्व का संकट। लोकतंत्र केवल चुनाव नहीं है, बल्कि जवाबदेही, नैतिकता और दूरदर्शिता भी है। आज कई देशों में नेतृत्व या तो अतिराष्ट्रवादी है, या फिर सत्ता से चिपके रहने के लिए हर हथकंडा अपनाने को तैयार। विचारधाराएं भी कठोर खांचों में बंध गई हैं। संवाद की जगह आरोप ने ले ली है। कूटनीति की जगह ट्वीट और धमकी ने। एक और गंभीर पहलू है—सूचना युद्ध और प्रोपेगेंडा। पहले युद्ध मैदान में लड़े जाते थे, अब दिमागों में भी लड़े जाते हैं। सोशल मीडिया, फेक न्यूज, डिजिटल प्रोपेगेंडा के जरिए नफरत और डर फैलाना आसान हो गया है। जनता को भावनात्मक रूप से तैयार किया जाता है ताकि युद्ध को नैतिक ठहराया जा सके। सच, आधा सच और झूठ का ऐसा मिश्रण पेश किया जाता है कि आम आदमी भ्रमित हो जाए। यह भी देखने की बात है कि दुनिया में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं—जैसे संयुक्त राष्ट्र—कमज़ोर पड़ती दिख रही हैं। बड़े देश अपने हितों के आगे वैश्विक नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं। वीटो पावर, गुटबंदी और भू-राजनीतिक खेमेबंदी ने सामूहिक निर्णय को कठिन बना दिया है। शांति स्थापना की प्रक्रियाएं लंबी और जटिल हैं, जबकि युद्ध का बटन दबाना आसान। इन सबके बीच सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? आम इंसान का। युद्ध नेताओं के भाषणों में शौर्य बनता है, लेकिन जमीन पर वह मातम होता है। मरने वाले सैनिक भी आम घरों के बेटे होते हैं और मरने वाले नागरिक भी। शहर खंडहर होते हैं, पीढ़ियां मानसिक आघात झेलती हैं, अर्थव्यवस्था बिखर जाती है, शिक्षा और स्वास्थ्य ढह जाते हैं। युद्ध केवल वर्तमान नहीं मारता, भविष्य भी घायल कर देता है। कभी-कभी यह सवाल भी उठता है—क्या यह सब पूंजीवाद की अंधी दौड़ का नतीजा है? क्या मुनाफे की भूख ने नैतिकता को पीछे छोड़ दिया है? जब बाजार सर्वोच्च मूल्य बन जाए और इंसान केवल उपभोक्ता, तब युद्ध भी 'स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट' जैसा लगने लगता है। यह सोच खतरनाक है, क्योंकि इसमें जीवन की कीमत बैलेंस शीट से तय होती है। विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्वयुद्ध को "फ्यूटाइल वॉर"—बेमानी युद्ध—कहा था, जिसे रोका जा सकता था। इतिहासकार भी मानते हैं कि संवाद, समझौते और समय रहते कदम उठाए जाते तो वह महाविनाश टल सकता था। यही बात आज भी लागू होती है। अधिकांश युद्ध अचानक नहीं होते, वे धीरे-धीरे तैयार होते हैं—भाषा से, बयान से, नीतियों से, हथियारों की खरीद से, अविश्वास से।

तो क्या रास्ता है?

सबसे पहला रास्ता है—संवाद और कूटनीति। बातचीत कमज़ोरी नहीं, समझदारी है। दुश्मनी स्थायी नहीं होती, हित स्थायी होते हैं।

खुद की सजगता ही बचा सकती है साइबर ठगी से डिजिटल दौर में सुरक्षित रहने का मंत्र सबके लिए जरूरी

-ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ते खतरे बीच जानिए बचाव के आसान और असरदार तरीके हर यूजर जरूर

डिजिटल दौर ने हमारे जीवन को जितना आसान बनाया है, उतना ही जटिल भी। मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ऑनलाइन शॉपिंग, ई-गवर्नेंस और सोशल मीडिया ने रोज़मर्रा के कामों को तेज, सरल और सुविधाजनक बना दिया है। आज घर बैठे बिल भरना, पैसा ट्रांसफर करना, निवेश करना और सरकारी सेवाओं का लाभ लेना संभव है। लेकिन इस डिजिटल क्रांति का एक खतरनाक पहलू भी है—साइबर ठगी। तकनीक का गलत इस्तेमाल कर ठग लोगों की गाढ़ी कमाई को मिनटों में साफ कर देते हैं। हालात इतने चिंताजनक हो चुके हैं कि डिजिटल ठगी से देशभर में अब तक हजारों करोड़ रुपये की रकम गायब हो चुकी है। यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि भरोसे, सुरक्षा और व्यवस्था पर भी चोट है। साइबर अपराधियों का जाल तेजी से फैल रहा है। वे अब पारंपरिक अपराधियों की तरह नहीं दिखते, बल्कि पढ़े-लिखे, तकनीक समझने वाले और मनोविज्ञान का इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं। वे सिस्टम की खामियों से ज्यादा इंसानी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। लालच, डर, जल्दबाजी और अज्ञानता उनके सबसे बड़े हथियार हैं। यही वजह है कि साइबर ठगी की रोकथाम सिर्फ तकनीकी उपायों से नहीं, बल्कि जन-जागरूकता और व्यक्तिगत सजगता से ही संभव है।

डिजिटल ठगी: बदलता हुआ खतरा

पहले ठगी का मतलब जेब काटना, नकली नोट या धोखाधड़ी वाले कागज़ात होता था। आज ठगी का चेहरा डिजिटल हो गया है। अब ठग आपके मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया और बैंक खाते के जरिए वार करते हैं। वे फर्जी वेबसाइट, नकली ऐप, स्पूफ कॉल और धोखाधड़ी वाले लिंक के जरिए लोगों को जाल में फंसाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर अपराधी अब संगठित नेटवर्क के रूप में काम कर रहे हैं। उनके पास कॉल सेंटर जैसे सेटअप, स्क्रिप्ट, तकनीकी टूल और डेटा की लंबी सूची होती है। वे लाखों लोगों को एक साथ मैसेज या कॉल करते हैं और जो व्यक्ति थोड़ा भी असावधान होता है, वही उनका शिकार बन जाता है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गंभीर राष्ट्रीय समस्या माना है। अदालत ने साइबर फ्रॉड को "डिजिटल डकैती" और "ऑनलाइन लूट" जैसी संज्ञा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि इतने बड़े पैमाने पर हो रही ठगी सिर्फ अपराधियों की चालाकी नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरी का भी नतीजा है। बैंकों की लापरवाही या अंदरूनी मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को निर्देश दिए हैं कि साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए बनाए गए नियम और एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) को सख्ती से लागू किया जाए। यह टिप्पणी बताती है कि मामला अब व्यक्तिगत नुकसान से आगे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से जुड़ चुका है।

आरबीआई की एसओपी और उसका महत्व

भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए विस्तृत एसओपी तैयार की है। इसमें कहा गया है कि जैसे ही किसी संदिग्ध लेन-देन की जानकारी मिले, तुरंत कदम उठाए जाएं। जैसे— संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर रोक, डेबिट/क्रेडिट कार्ड को अस्थायी रूप से होल्ड करना, खाते की गतिविधियों को सीमित करना, समयबद्ध जांच, ग्राहक को तुरंत अलर्ट, इन नियमों का मकसद यह है कि नुकसान को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके। लेकिन समस्या नियमों की कमी नहीं, बल्कि उनके ढीले पालन की है। कई मामलों में शिकायत के बाद भी कार्रवाई देर से होती है, जिससे ठग रकम को कई खातों में घुमाकर गायब कर देते हैं।

ठगी का मनोविज्ञान: दिमाग पर हमला

साइबर ठग सीधे आपके बैंक खाते पर नहीं, आपके दिमाग पर हमला करते हैं। वे ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि व्यक्ति सोचने-समझने की ताकत खो देता है। आमतौर पर तीन तरीके सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं—

लालच का जाल: "आपने लॉटरी जीती है", "निवेश करें और पैसा दोगुना पाएं", "सरकारी योजना में बोनस" — ऐसे ऑफर लोगों को आकर्षित करते हैं।

डर का दबाव: "आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा", "केवाईसी अपडेट नहीं किया", "आप पर केस दर्ज है" — डर पैदा कर तुरंत कार्रवाई के लिए मजबूर किया जाता है।

जल्दबाजी की रणनीति: "अभी क्लिक करें", "10 मिनट में वेरिफिकेशन", "तुरंत भुगतान करें" — सोचने का समय नहीं दिया जाता। जब व्यक्ति भावनात्मक दबाव में आ जाता है, तो ठग आसानी से उससे ओटीपी, पिन या पैसे निकलवा लेते हैं।

डिजिटल अरेस्ट: नया खतरनाक ट्रेंड

हाल के समय में "डिजिटल अरेस्ट" नाम का नया फ्रॉड सामने आया है। इसमें ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं। वे कहते हैं कि आपके खिलाफ केस है और आपको तुरंत सहयोग करना होगा, वरना गिरफ्तारी होगी। कई बार नकली आईडी, फर्जी वर्दी और बैकग्राउंड सेटअप भी दिखाया जाता है। लोग डर के कारण उनकी बात मान लेते हैं और "जांच" के नाम पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। यह पूरी तरह फर्जी होता है। कोई भी सरकारी एजेंसी वीडियो कॉल पर पूछताछ कर पैसे नहीं मांगती।

फर्जी लॉटरी और सरकारी योजना ठगी

एक और आम तरीका है सरकारी योजना या लॉटरी के नाम पर ठगी। ठग मैसेज भेजते हैं कि आपने बड़ी इनामी राशि जीती है। फिर कहते हैं कि प्रोसेसिंग फीस, टैक्स या रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करें। एक बार पैसा भेजने के बाद नई-नई फीस के नाम पर और रकम मांगी जाती है। अंत में संपर्क टूट जाता है। याद रखिए—सरकारी योजनाएं कभी फीस लेकर इनाम नहीं देतीं, और असली लॉटरी जीतने पर पहले से पैसा जमा नहीं करना पड़ता।

डोटासरा का बजट पर हमला:
विकास का रोडमैप गायब, किसानों-युवाओं-शिक्षा पर सरकार रही मौन

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार के बजट को निराशाजनक बताते हुये कहा कि बजट में प्रदेश की प्रगति और विकास के लिये किसी प्रकार की अपेक्षित योजना हेतु राशि आवंटित नहीं होने से प्रदेशवासियों में मायूसी व्याप्त है। बजट में एक बार पुनः यमुना जल परियोजना का जिक्र किया गया, किन्तु ना तो कोई राशि इस परियोजना के लिये आवंटित हुई और ना ही परियोजना कब प्रारम्भ होगी इस पर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार ईआरसीपी परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों के लिये कोई बजट आवंटन राशि का नहीं हुआ है। बजट में भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश की जमीन व लैण्ड बैंक के बंदरबाट के आरोप जो कांग्रेस ने लगाये थे वे सब सच साबित हुये हैं, जब सरकार ने प्रतिदिन 8 उद्योगों को भूमि आवंटित करने की स्वीकृति देना बताया है, जबकि कितने उद्योग स्थापित हुये और राईजिंग राजस्थान के तहत् कितनी राशि का निवेश प्रदेश को मिला है, साथ ही कितने रोजगार सृजित हुये, इस विषय पर बजट में सरकार पूरी तरह से मौन रही है। राजस्थान सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 3768 स्कूल भवन जर्जर हैं, कक्षा-कक्ष और शौचालयों में मरम्मत की आवश्यकता है, इनकी मरम्मत और सुधार के लिये 21 हजार करोड़ रूपये की आवश्यकता बताई गई है, किन्तु हाईकोर्ट द्वारा तल्ख टिप्पणी किये जाने के बावजूद सरकार ने मात्र 2500 विद्यालयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु 550 करोड़ रूपये व्यय करना प्रस्तावित किया है। साथ ही 300 भवन विहीन एवं जर्जर विद्यालयों के भवनों के निर्माण की लागत हेतु मात्र 450 करोड़ रूपये से निर्माण करवाना प्रस्तावित किया है, जो दर्शाता है कि राजस्थान की भाजपा सरकार सार्वजनिक शिक्षा के प्रति व विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के प्रति उदासीन है। बजट में किसानों से गेहूं की खरीद एमएसपी पर बोनस देकर 2750 की दर से खरीद करने की भी घोषणा नहीं की गई, ना ही बाजरे की एमएसपी पर खरीद करने की घोषणा की गई, जबकि ये वादे भाजपा ने चुनाव से पूर्व प्रदेश के किसानों से किये थे। बजट में राज्य सरकार की एक लाख भर्तियां प्रतिवर्ष करने की घोषणा के अनुरूप नई भर्तियों की कोई घोषणा नहीं हुई। राज्य सरकार के बजट में छात्रों को टेबलेट और लैपटॉप देने जैसी योजनाओं को पुनः समावेशित किया गया है, किन्तु बजट आधा कर दिया गया, जबकि पुरानी घोषणायें भी अभी तक अधूरी है और इस बजट में ई वाउचर के माध्यम से रूपये 20000 की राशि देने की घोषणा की गई है जो कि नाकाफी है। सरकार द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तर्ज पर राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी स्थापित करने की घोषणा की गई है, यह घोषणा पूर्व में भी सरकार द्वारा की गई थी, किन्तु इस योजना ने मूर्त रूप नहीं लिया था। बजट में कोई नवीन महाविद्यालय या चिकित्सालय खोलने जैसी घोषणा नहीं हुई है बल्कि पिछले बजट में जयपुर में आधारभूत सुविधायें के निर्माण सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में इन्फ्रास्टक्कर निर्माण करने की घोषणायें फिजीबल नहीं होने के आधार पर निरस्त कर दी गई। ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर खेल के आयोजन के लिये आवंटित 50 करोड़ नाकाफी हैं। इसी प्रकार अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी भवनों की मरम्मत हेतु बजट में आवंटित 500 करोड़ रूपये ऊंट के मुँह में जीरा समान है। बजट केवल पुरानी चली आ रही योजनाओं के क्रियान्वयन और छोटे-मोटे बदलावों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रदेश के विकास का रोड मैप नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को प्रस्तुत बजट निराश करने वाला है।

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह

-स्काउट व गाइड संगठन युवाओं की सेवा संकल्प से जुड़ी संस्कृति- राज्यपाल

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि युवा स्वयं के विकास के साथ राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें। उन्होंने स्काउट गाइड संगठन के युवाओं को दृढ़ संकल्प शक्ति और मन बनाकर समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं को अधिकारों की बजाय राष्ट्र और समाज तथा शिक्षा के प्रति कर्तव्य की भावना को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। बागडे राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्काउट व गाइड संगठन युवाओं की सेवा संकल्प से जुड़ी संस्कृति से जुड़ा संगठन है। उन्होंने राजस्थान को योद्धाओं की भूमि बताते हुए कहा कि यहां का व्यक्ति शौर्य, वीरता और साहस से जुड़ा है। यहां निरंतर लड़ाइयाँ हुई पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण की भावना रही है। उन्होंने सेना में यहां के सर्वाधिक युवाओं के होने की चर्चा करते हुए स्काउट गाइड से जुड़े युवाओं को अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़े रहने का आह्वान किया। उन्होंने आपात काल में स्काउट गाइड की रही भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि वह स्वयं स्काउट संगठन में रहे हैं। यह अनुशासन से जुड़ा युवाओं को प्रेरणा देने वाला संगठन है। समारोह में विधायक दर्शन सिंह और वीरेंद्र सिंह, अखिल शुक्ला ने भी विचार रखें। स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य ने राजस्थान में संगठन की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इससे पहले राज्यपाल ने श्रेष्ठ स्काउट गाइड को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। स्काउट गाइड ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां के साथ साहसिक कैंप आदि से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन किया।

विशेष निरोधात्मक अभियान - प्रदेश में 2 लाख 34 हजार लीटर से अधिक वॉश नष्ट

-निरोधात्मक कार्रवाई में 894 केस दर्ज - 718 गिरफ्तार

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोक लगाने हेतु जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए जनवरी माह में 2 लाख 34 हजार 371 लीटर वॉश नष्ट किया गया। इसी क्रम में विभिन्न निरोधात्मक कार्यवाही में 894 केस दर्ज करते हुए 718 को गिरफ्तार किया गया। आबकारी आयुक्त के अनुसार प्रदेश में जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की गई। प्रदेश में जनवरी माह में 2 लाख 34 हजार 371 लीटर वॉश नष्ट किया गया। इसी क्रम में भारत निर्मित विदेशी मदिरा 622, देशी मदिरा 4921, अवैध मदिरा 5468, बीयर 1052 बोतल सहित एक किलोग्राम भांग को सीज किया गया। प्रदेश में विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत जनवरी माह में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय में संलिप्तता पर राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत 894 केस दर्ज करते हुए 718 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध मदिरा परिवहन में प्रयुक्त 33 दुपहिया वाहन, 3 हल्के चार पहिया वाहन, 3 भारी चार पहिया वाहन एवं एक अन्य सहित 40 वाहनों को सीज किया गया है।

दौसा में हज प्रशिक्षण व टिकाकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया

मनोहरपूर (रॉयल पत्रिका)। सेंट हाफिज स्कूल शेखान मोहल्ला दौसा में जिला हज कमेटी दौसा के सौजन्य से हज प्रशिक्षण व टिकाकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे हज सफ़र 2026 पर दौसा जिले से जा रहे 09 हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने जयपुर से आए प्रशिक्षक जनाब हाजी शाहिद मौहम्मद पूर्व सदस्य, हाजी डॉ. अशफाक नक़वी, हाजी अब्दुल नफिस, हाजी मौहम्मद परवेज़, फरीदउद्दीन, ने हज और उमराह के बारे मे जानकारी दी एवं चिकित्सा विभाग से आए चिकित्सकों ने 09 हाजियों का टिकाकरण किया। हाजी मेहराज हाशमी ने बताया कि इस प्रोग्राम के दौसा जिला संयोजक हाजी मोहम्मद ज़ाकिर, जिला सह संयोजक हाजी मोहम्मद मेहराज, हाजी यूसुफ खान, मौलवी नसरुद्दीन, सूफ़ी अब्दुल लतीफ, मौलाना तौसीफ, जाबिर खान पार्षद आसीफ खान नेता, नोमान खान, अब्दुल समद, अयान खान, रेहान हाशमी हाजी अरकान, अजहर खान मौजूद रहे।

'सक्षम साथिन' पहल से महिला सशक्तिकरण को मिल रही नई दिशा

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। महिला अधिकारिता विभाग एवं एजुकेट गर्ल्स की साझा पहल के तहत जयपुर में 'सक्षम साथिन कार्यशाला' का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले की लगभग 40 साथिनों एवं सुपरवाइजर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य साथिन बहनों को सरकारी योजनाओं, उच्च शिक्षा के अवसरों तथा आधुनिक तकनीकी विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था। कार्यक्रम का शुभारंभ राजेश डोगीवाल, उप निदेशक, महिला अधिकारिता, जयपुर के मार्गदर्शन में हुआ। एजुकेट गर्ल्स की ओर से श्रीमती लवीना राठौड़, प्रोजेक्ट लीड ने अतिथि प्रवीण सिन्हा, जेंडर स्पेशलिस्ट एवं उपस्थित साथिनों का स्वागत किया। प्रवीण सिन्हा ने विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं महिला सशक्तिकरण से संबंधित पहलों पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा साथिनों को समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति प्रेरित किया। एजुकेट गर्ल्स की रूपाली शर्मा ने वर्तमान में बढ़ते साइबर फ्रॉड के मामलों एवं उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दी। रजत शर्मा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मूलभूत अवधारणाओं तथा डिजिटल टूल्स के प्रभावी उपयोग के महत्व से प्रतिभागियों को अवगत कराया। रूपाली एवं तान्या ने विभिन्न सहभागितापूर्ण गतिविधियों के माध्यम से संचार कौशल के महत्व को रेखांकित किया। कार्यशाला के दौरान कुछ साथिनों ने अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड के अनुभव भी साझा किए, जिससे विषय की गंभीरता और प्रासंगिकता स्पष्ट हुई। कार्यक्रम के अंत में एजुकेट गर्ल्स टीम ने साथिनों को आत्मनिर्भर बनने तथा अर्जित ज्ञान का समाज हित में सदुपयोग करने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला का समापन प्रमाण पत्र वितरण एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक बताया। यह पहल जिले में साथिनों को तकनीकी रूप से सशक्त कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

अवैध गैस रिफिलिंग गिरोह का भंडाफोड़, दो मुल्जिम गिरफतार

-मुल्जिमान के कब्जे से 52 घरेलू गैस सलैण्डर बरामद

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। संजीव नैन आईपीएस पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व ने बताया कि, सांगानेर क्षेत्र में घरेलू गैस सलैण्डरों से ऑटो रिक्शा में गैस रिफलिंग का अवैध कार्य किया जा रहा था। जिस पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व आलोक सिंघल आरपीएस अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व के निर्देशन में हरि शंकर शर्मा आरपीएस सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर के निकट सुपरविजन में लिखमाराम पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना सांगानेर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। सूर्य नगर तारों की कुंट बी 2 बायपास के पास एक खाली प्लाट में अवैध गैस रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था जिस पर डीएसओ एवं गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए कुल 13 घरेलू गैस सलैण्डर एवं 4 इलेक्ट्रिक कांटे जप्त किये जाकर मुल्जिम अनिल विश्नोई को गिरफ्तार किया गया एवं दूसरी कार्यवाही नारायण विहार सैक्टर नं 03 प्रताप नगर में करते हुए कुल 39 घरेलू गैस सलैण्डर जप्त किये गये जिनमें 29 खाली व 10 भरे हुए थे एवं सलैण्डरों को लाने ले जाने के लिए काम में ली जाने वाली पिकअप गाडी को भी जप्त किया जाकर मुल्जिम दिनेश विश्नोई को गिरफतार किया गया मुल्जिम दिनेश विश्नोई के खिलाफ पूर्व में भी मारपीट व अवैध गैस रिफलिंग के प्रकरण दर्ज है। मुल्जिमान के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दो अलग अलग प्रकरण दर्ज किये।

जनगणना राष्ट्रीय दायित्व, गुणवत्ता से न हो कोई समझौता - विष्णु चरण मलिक

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। भारत की जनगणना–2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण के दूसरे दिन निदेशक एवं मुख्य प्रमुख जनगणना अधिकारी विष्णु चरण मलिक ने चार्ज जनगणना अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए। प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कार्यशाला में निदेशक मलिक का स्वागत किया तथा प्रशिक्षण की प्रगति से अवगत कराया। इस अवसर पर विष्णु चरण मलिक ने कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, जिसकी गुणवत्ता सीधे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने वाले आंकड़ों की शुद्धता से जुड़ी होती है। उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना आधुनिक एवं पूर्णतः डिजिटल स्वरूप में संपादित की जाएगी, जिससे डाटा की शुद्धता, पारदर्शिता एवं त्वरित विश्लेषण सुनिश्चित होगा। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में चार्ज अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी और उन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सजगता एवं जिम्मेदारी के साथ करना होगा। प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने 10 फरवरी 2026 को प्रशिक्षण में उपस्थित रहकर चार्ज एवं अतिरिक्त चार्ज अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनगणना–2027 के कार्य को पूर्ण गंभीरता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ संपादित करें, ताकि समस्त कार्य सीएमएमएस पोर्टल (जनगणना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण प्रणाली) पर सही एवं त्रुटिरहित रूप से सम्पन्न हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनगणना जैसे व्यापक और संवेदनशील कार्य में तकनीकी दक्षता, समन्वय एवं समयबद्धता अत्यंत आवश्यक है, जिससे जिले में जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सके।

प्रभावी टीका प्रबंधन पर दो दिवसीय कार्यशाला

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत विभिन्न टीकों की मांग, आपूर्ति, गुणवत्ता व प्रभावी मॉनिटरिंग के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण संस्थान (शिफू) में प्रभावी टीका प्रबंधन (ईवीएम) पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला में जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारियों, वैक्सीन स्टोर इंचार्ज सहित अन्य कार्मिकों ने सहभागिता की। मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. अमित कुमार यादव ने बताया कि राज्य सरकार संसाधनों के कुशल उपयोग और मजबूत वितरण प्रणाली के माध्यम से अंतिम लाभार्थी तक सुरक्षित टीके पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में केन्द्रीय एवं राज्य स्तर से आपूर्ति किये जा रहे टीकों की सुगम व सुरक्षित स्टोरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी टीका प्रबंधन (ईवीएम) अपनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में ईवीएम के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, गुणवत्ता मॉनिटरिंग, गेप-एनेलेसिस-आईडेंटीफिकेशन, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सहित अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला में निदेशक आरसीएच डॉ.मधु रतेश्वर, राज्य कोल्ड चैन अधिकारी डॉ. मनीषा चौधरी व संबंधित अधिकारीगण भी मौजूद रहे।

सूर्यकिरण एरोबेटिक शो की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ली बैठक

-22 फरवरी को जलमहल पर प्रस्तावित है एयर शो

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। जयपुर में भारतीय वायु सेना की विश्वप्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम द्वारा 22 फरवरी को एयर शो आयोजन प्रस्तावित है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर आत्माराम सावंत ने वायु सेना, पुलिस, सामान्य प्रशासन विभाग, पर्यटन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक में कार्यक्रम की तिथि, स्थल, ट्रैफिक व पार्किंग व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर बैठक व्यवस्था तथा सुरक्षा इंतजामों पर विस्तार से चर्चा की गई। भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन विनय भारद्वाज ने बताया कि सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के 11 फाइटर जेट तथा सारंग टीम के 6 हेलीकॉप्टर अपने सटीक समन्वय और रंगीन धुएं के आकर्षक पैटर्न के माध्यम से दर्शकों को रोमांचित करेंगे। कार्यक्रम में 75 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए पूरे आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी तथा यातायात व्यवस्था के विशेष प्रबंध किए जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन ने सामान्य प्रशासन विभाग एवं जयपुर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव को दी। बैठक में जयपुर संभागीय आयुक्त श्रीमती पूनम, पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल, जेडीसी सिद्धार्थ महाजन, जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी, पर्यटन आयुक्त श्रीमती रूक्मणि रियार, नगर निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार, पुलिस उपायुक्त (यातायात) सुमित मेहरडा सहित पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, परिवहन एवं जेडीए के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश में सुदृढ़ होंगी अंगदान एवं प्रत्यारोपण की प्रक्रियाएं

-लाइव पोर्टल से जुड़ेंगे सभी अस्पताल, विजिलेंस सिस्टम भी होगा मजबूत

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। प्रदेश में अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण सेवाओं को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने के लिए प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन संचालित किया जाएगा। इसके लिए नव विकसित लाइव पोर्टल जल्द शुरू किया जाएगा। अंगदान एवं प्रत्यारोपण करने वाले सभी अस्पतालों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि अंगदान एवं प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और सभी जानकारियां इस पर उपलब्ध हों। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण जीवन रक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। प्रदेश में इससे जुड़ी सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मानक प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने के साथ ही विजिलेंस सिस्टम को सुदृढ़ बनाया जाएगा। श्रीमती राठौड़ ने कहा कि अंगदान एवं प्रत्यारोपण के कार्यों के लिए निदेशालय स्तर पर गठित प्रकोष्ठ को और सुदृढ़ किया जाएगा। यह प्रकोष्ठ नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी अस्पतालों में अंगदान एवं प्रत्यारोपण की प्रक्रियाएं एसओपी के अनुरूप हों और उन अस्पतालों में इन कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। साथ ही,सभी महत्वपूर्ण जानकारियां पोर्टल पर अपडेट हों।

सीएचसी स्तर तक स्वास्थ्यकर्मियों को किया जाए प्रशिक्षित-

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए मेडिकल कॉलेज से लेकर ट्रोमा सेंटर एवं सीएचसी स्तर तक स्वास्थ्यकर्मियों एवं एम्बुलेंसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही, आमजन एवं स्वास्थ्यकर्मियों में इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाए।

जनसमस्या निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें-

प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वे जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जनसुनवाई, सम्पर्क पोर्टल, 181 हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री कार्यालय या अन्य माध्यमों से प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही, शिकायतकर्ता से बात कर समस्या समाधान का फीडबैक भी प्राप्त करें। उन्होंने ग्रिवांस रिडरेसल सिस्टम को मजबूत बनाने और इसके लिए तकनीकी नवाचारों को अपनाने पर भी बल दिया।

बेहतर सर्विस डिलीवरी पर करें फोकस-

श्रीमती राठौड़ ने कहा कि अधिकारी स्वयं के स्टाफ की समस्याओं का भी समय पर निस्तारण कर उन्हें राहत प्रदान करें। कार्यालय परिसर में साफ—सफाई, रंग—रोगन एवं नियमित मेंटीनेंस के कार्यों पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कार्मिक बेहतर सर्विस डिलीवरी पर फोकस करते हुए आमजन को विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों का पूरा लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।

बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव, अतिरिक्त मिशन निदेशक डॉ. टी. शुभमंगला, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निधि पटेल, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त नरेश गोयल, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

आवश्यक नम्बर

रॉयल पत्रिका

बिजली फॉल्ट के लिए

टोल फ्री नंबर	18001806507
वॉट्सएप नंबर	9414037085
कस्टमर केयर	2203000
आईवीआरएस	1912

कचरा गाड़ी के लिए

ग्रेटर	2747400
सीवरेज लीकेज	2607500
हेरिटेज	2607500
टोल फ्री नंबर	14420

पुलिस की मदद के लिए

साइबर क्राइम	1930/2360094
कंट्रोल रूम	2388435/36/37/38
ट्रैफिक कंट्रोल रूम	2565630
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098
महिला हेल्पलाइन	1090
मुख्यमंत्री पोर्टल	181

पानी के लिए

जलदाय कार्यालय	2706624
फायर ब्रिगेड	2747400

मेडिकल इमरजेंसी के लिए

एंबुलेंस	102/108
एसएमएस इमरजेंसी	2518333
महिला चिकित्सालय	22610616
जनाना हॉस्पिटल	22378721
SDMH	22574189
SMS ब्लड बैंक	22518222
कल्याण ब्लड बैंक	22721771

घायल पशुओं के लिए

नगर निगम	2747400
बर्ड बाइक	9887345580
हेल्प इन सफरिंग	8107299711
जनमंच ट्रस्ट	7230055800
पशु चिकित्सालय	2747400

गोलूवाला में वार्ड समस्याओं को लेकर भाजपा नेताओं ने सौंपा ज्ञापन

-सड़क निर्माण में अनियमितता की जांच की मांग

विनोद सोखल

हनुमानगढ़/गोलूवाला (रॉयल पत्रिका)। भाजपा नेता हंसराज भुवांल के नेतृत्व में गोलूवाला मंडल अध्यक्ष सीताराम थापन व मंडल पदाधिकारियों ने वार्डों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिशासी अधिकारी (ईओ) कृष्णा कुमारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वार्डों में व्याप्त मूलभूत समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि नगरपालिका क्षेत्र में हाल ही में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में एक फर्म द्वारा पुरानी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। वार्डवासियों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने

की मांग उठाई है। इसके अलावा पिछले बरसाती सीजन में शहर से पानी निकासी का कार्य करने वाले ट्रैक्टर मालिकों को भुगतान नहीं किए जाने तथा किसी अन्य फर्म को गलत तरीके से भुगतान कर राशि हड़पने के आरोपों की भी जांच की मांग की गई है। भाजपा नेताओं ने कहा कि यदि मामले की सही जांच नहीं की गई तो राज्य सरकार स्तर पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाएगी। ईओ कृष्णा कुमारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सभी शिकायतों की जांच कर शीघ्र समस्या का समाधान किया जाएगा। इस दौरान सुरेन्द्र सिहाग, राजेन्द्र मांझू, जगदीश वर्मा, पवन सोनी सहित अनेक नागरिक मौजूद रहे।

ऑन ड्यूटी महिला थाना प्रभारी ज्योति नायक का सर्वोच्च बलिदान

-दुर्गा मंदिर के नजदीक पुलिस जीप में कार ने मारी टक्कर, ड्राइवर सहित दो घायल

विनोद सोखल

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में महिला थाना प्रभारी ज्योति नायक ने ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दे दिया। हादसा सुबह करीब 4 बजे दुर्गा मंदिर रोड पर उस समय हुआ, जब वे पुलिस टीम के साथ गश्त पर थी। मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस जीप किसान चौक की ओर से दुर्गा मंदिर की तरफ जा रही थी। जीप को कांस्टेबल अजय कुमार चला रहे थे। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आई एक कार ने पुलिस वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस जीप पलट गई। हादसे में थाना प्रभारी ज्योति नायक गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि जीप चालक अजय कुमार और कार चालक भी घायल हो गए। तीनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने ज्योति नायक को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, सिर में गहरी चोट लगने के कारण उनकी मौत हुई। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी पृथ्वीपाल सिंह सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने भी अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हादसे की खबर मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार हरियाणा नंबर की बताई जा रही है और तेज रफ्तार के कारण नियंत्रण खो बैठी। फिलहाल कार चालक का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि:-

पोस्टमार्टम के बाद ज्योति नायक

के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन लाया गया, जहां गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दोपहर बाद उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। ज्योति नायक अपने कर्तव्यनिष्ठ, साहसी और दबंग छवि के लिए जानी जाती थीं। उनके आकस्मिक निधन से न केवल पुलिस विभाग बल्कि पूरे शहर में शोक की लहर लहर दौड़ पड़ी। जानकारी अनुसार श्रीमती ज्योति नायक पूर्व मंत्री दुल्लाराम नायक की दोहती और दौलतराज नायक की भानजी थी। ज्योति नायक का पति एडवोकेट है, जिसके एक पुत्री भी है। ज्योति नायक हनुमानगढ़ जिले में ब्याही हुई थी। समाचार लिखे जाने तक इस सम्बन्ध में मुकद्दमा दर्ज नहीं हुआ था। ज्योति नायक महिला थाना से पहले पुरानी आबादी सहित अन्य थानों में भी तैनात रही थी।

दिव्यांग छात्र-छात्राओं ने किया रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण

-भालू की चहल कदमी देखकर खास रोमांचित हुए विशेष बच्चे

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर संचालित मुस्कान विशेष विद्यालय के दिव्यांग छात्र छात्राओं को रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कराया गया। संस्था सचिव अरविंद चौहान के बताया की दिव्यांग बच्चों को हर साल रणथंभौर नेशनल पार्क का शैक्षिक भ्रमण कराकर बच्चों को वन एवं वन्यजीवों की जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज वन विभाग की 'बाघ रक्षक' योजना के तहत उपवन संरक्षक मानस सिंह के द्वारा विशेष बच्चों को जंगल भ्रमण की स्वीकृति मिलने के बाद बच्चों को जोन न. 6 में विजिट कराई गई। विजिट के दौरान स्पेशल एडुकेटर सचिन सिंह, हनुमान

गुर्जर, अमिता मीणा, सुरेन्द्र सिंह, श्याम सुंदर रेगर, सुरेन्द्र रेगर, द्वारा बच्चों को चीतल, हिरण, सांभर, बंदर, भालू आदि की जानकरी दी गयी। बच्चों की टाइगर की सइटिंग नही होने से बच्चे मायूस नजर आए। लेकिन जॉन 6 में पटवा बावड़ी के पास स्लोथ बियर (भालू) की चहल कदमी देख बच्चें खासा रोमांचित हो उठे। वार्डेन भानु प्रताप सिंह एवं हेल्पर युवराज सिंह ने सभी बच्चों के लिए जलपान की व्यवस्था की। जिससे बच्चों को अलग ही आनंद आया। कैंटर चालक रत्तीराम मीणा, सुमेर सिंह चौधरी ने बच्चों को बड़ी सहूलियत के साथ जंगल का भ्रमण कराया। दिव्यांग छात्र छात्राओं को पार्क विजिट कराने पर संस्था सचिव ने सभी लोगो को धन्यवाद दिया।

महीने बाद मिला लहराता परिवार, महवा के बालक की घर वापसी

शफीक अली

महवा (रॉयल पत्रिका) । एक प्रयास घर वापसी का अभियान और रक्तदाता फूलसिंह नागर दूल्हापूरा एवं रजनीश जैन और अजय झा की मेहनत से हुआ संभव। दौसा महवा के 3 महीने पहले ट्रेन में छूटा एक बालक राजस्थान से दिल्ली पहुंच गया था। एक प्रयास घर वापसी का अभियान के अजय झा सर ने इस बालक का केस लिया और उसकी काउंसलिंग की। बालक महवा में अपना घर बता रहा था और जयपुर का जिक्र कर रहा था, जिससे राजस्थान के दौसा महवा का एरिया ध्यान में आया। समाजसेवी रक्तदाता फूलसिंह नागर दूल्हापूरा महवा दौसा ने बच्चे की काउंसलिंग वीडियो को महवा के हर गांव में प्रसारित करवाया और आखिरकार 24 घंटे बाद बालक के चाचा और पिताजी से बात हुई। बात करने पर पता

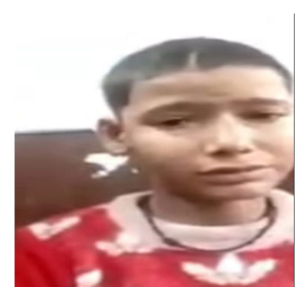

चला कि बालक को उसकी मानसिक रूप से अस्वस्थ मां रात को लेकर घर से निकल गई थी और तब से ही परिवार इनकी तलाश कर रहा था। मां का पता जोधपुर में मिल गया था, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल पा रहा था। इस सुखद पुनर्वास हेतु फूल सिंह नागर महवा और अजय झा सर का तहे दिल से धन्यवाद। रजनीश जैन, संस्थापक एक प्रयास घर वापसी का अभियान ने कहा कि यह एक खुशी का क्षण है जब हम बालक को उसके परिवार से मिलवा पाए।

पाली जिले के 61 हज यात्रियों का टीकाकरण, मेडिकल व प्रशिक्षण हुआ सम्पन्न

मोहम्मद यासीन

पाली (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के आदेशानुसार हज 2026 के लिए चयनित पाली जिले के 61 हज यात्रियों का टीकाकरण,मेडिकल एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम पुराना बस स्टैंड स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाना में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन हज यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुचारु बनाने के उद्देश्य से किया गया। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के हज ट्रेनर पूर्व पार्षद आमीन अली रंगरेज ने शिविर में हज यात्रियों को हज सुविधा ऐप तथा स्मार्टवाच की जानकारी दी। रंगरेज ने बताया कि केम्प में हाजियों का टीकाकरण किया गया तथा उनकी मेडिकल जांच कर मेडिकल डायरी दी गई। साथ ही यात्रियों को हज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां एवं दिशा-निर्देश प्रदान किए। प्रशिक्षण सत्र में उलेमाओ काज़ी इकरामुद्दीन जोधपुर, हाजी अब्दुल जब्बार जोधपुर, हज ट्रेनर आमीन अली रंगरेज पाली, हाजी मोहम्मद साबिर

राजसमन्द, कयूम मोदी जोधपुर ने हज की प्रक्रिया, एहतियात, अनुशासन एवं यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी। टीकाकरण एवं मेडिकल जांच का कार्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की डॉ उजमा जबीन एवं मेडिकल टीम द्वारा किया गया। शिविर में जिला अल्पसंख्यक मामलात विभाग के स्टाफ का भी सहयोग रहा। कार्यक्रम में हाजी अनवर चौहान सुहाना, अमजद अली अल्फ़ाज़ का विशेष सहयोग रहा। वहीं हज कमेटी के एडवोकेट साबिर खान, अल्ताफ अहमद चूड़ीगर, शाहिद पीनू, अमजद अली रॉयल, हाजी महबूब टी, तारिक चूड़ीगर, रमजान सामरिया, यूसुफ मोयल, एडवोकेट असलम खान, मोहम्मद यासीन रॉयल,जिशान अली रंगरेज, मोनू भाई चूड़ीगर, जावेद सिरोहा, अनवर हुसैन सोजत, यूनुस दर्द, अनीश पठान, नादिर हुसैन, आसिफ अली सहित कमेटी सदस्यों ने सेवाएं दी। शिविर में हज यात्रियों के लिए चाय-नाश्ता एवं दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई। साथ ही सभी हाजियों को हज कीट भी प्रदान किया गया।

बजट में रोजगार सृजन का कोई स्पष्ट और समयबद्ध रोड मैप दिखाई नहीं देता- रफीक मंडेलिया

मोहम्मद अली पठान

चूरू (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष रफ़ीक मंडेलिया ने कहा, राजस्थान सरकार का यह बजट केन्द्रीय बजट की तरह ही आमजन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। प्रदेश का युवा लंबे समय से रोजगार, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और स्थायी अवसरों की आस लगाए बैठा था, लेकिन बजट में रोजगार सृजन का कोई स्पष्ट और समयबद्ध रोडमैप दिखाई नहीं देता। मंडेलिया ने कहा निजी क्षेत्र में निवेश और उद्योग विस्तार के जरिए रोजगार बढ़ाने की ठोस नीति का अभाव साफ नजर आता

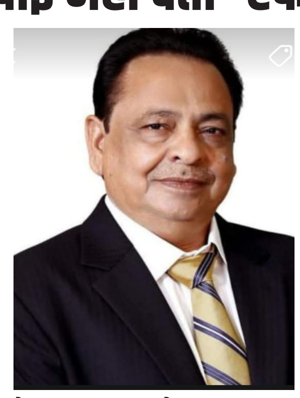

है। महिला सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर सरकार कोई विशेष कानून या मजबूत व्यवस्था प्रस्तुत नहीं कर पाई। चूरू जिले में औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देने, ख़स्ताहाल सड़को की मरम्मत, मेडिकल कॉलेज से जुडे जिले के सबसे बड़े अस्पताल में हृदय रोग विशेषज्ञ की नई ब्रांच खोलने जैसी कोई भी घोषणा नहीं की गई। कांग्रेस नेता ने कहा भाजपा 'नहीं सहेगा राजस्थान' के नारे के साथ सत्ता में आई भाजपा सरकार ने किसान कर्जामुक्ति, खाद-बीज की सुलभ उपलब्धता, और उर्वरक की बढ़ती कीमतों पर एक भी ठोस बात नहीं की, जिससे अन्नदाता का अपमान हुआ है। राजस्थान का हर वर्ग—युवा, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला, कर्मचारी—अब राजस्थान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठा है।

मांझूवास जीएसएस में भीषण आग, मुख्य ट्रांसफार्मर जला - बिजली सप्लाई ठप

विनोद सोखल

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। श्रीगंगानगर जिले के मांझूवास गांव स्थित जीएसएस (ग्रिड सब स्टेशन) में बुधवार दोपहर भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, जिसने कुछ ही देर में मुख्य ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लिया। मांझूवास से 34 एलएलपी कच्चे रास्ते पर स्थित जीएसएस में लगी इस आग से मेन ट्रांसफार्मर पूरी तरह जल गया, जिससे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ट्रांसफार्मर के जलने से विद्त व्यवस्था बहाल होने में लंबा समय लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही विद्त विभाग के कनिष्ठ अभियंता, लाइनमैन और अन्य तकनीकी

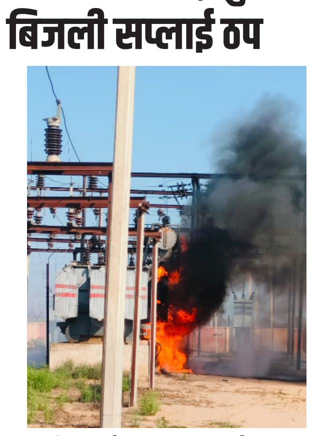

कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने तथा नुकसान का आकलन करने में जुट गए। आग से जीएसएस को भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल मांझूवास और आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती जारी है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का निरीक्षण

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा विचाराधीन प्रकरण डी.बी. सिविल रिट पीटिशन नंबर 18092/2023 उनवान लोक उत्थान संस्थान बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 29.01.2026 को पारित आदेश की पालना में समीक्षा गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर द्वारा बुधवार को मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह सवाई माधोपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 46 लोग आवासित पाये गयें। निरीक्षण के दौरान सचिव समीक्षा गौतम द्वारा पुनर्वास गृह के संचालन, आवासितों की संख्या, आवासितों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु डॉक्टर की विजिट, सरकार द्वारा प्रदत वित्तीय सहायता, अनुदान, पुनर्वास के कल्याण और बुनियादी ढांचे से संबंधित अन्य मुद्दों के संबंध में जानकारी ली गई। साथ ही आवासितों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना गया, साथ ही आवासितों के शारिरीक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने

हेतु आवासितों से सुझाव लिये गयें। निरीक्षण के दौरान आवासितों द्वारा बताया गया कि उन्हें बाहर घूमने नहीं जाने दिया जाता है, इस संबंध में पुनर्वास गृह के मैनेजर वीरसिंह गुर्जर द्वारा अवगत करवाया गया कि आवासितों को बाहर घूमने जाने से कोई भी अप्रिय घटना होने का अंदेश बना रहता है। निरीक्षण के दौरान आवासितों द्वारा पत्र, पत्रिकाएं एवं धार्मिक पुस्तकें पढ़ने तथा त्योहारों के अवसर पर पुनर्वास गृह में धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने एवं उनकी उम्र एवं शारिरीक क्षमता को मध्यनजर रखते हुए योग एवं इन्डोर गेम्स की इच्छा जाहिर की गई। इस संबंध में सचिव समीक्षा गौतम द्वारा पुनर्वास गृह के मैनेजर को मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्षम आवासितों को माह में एक बार धार्मिक या अन्य दर्शनीय स्थलों पर भ्रमण करवाये जाने, आवासितों को पढ़ने के लिये पत्र, पत्रिकाएं, धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध करवाने, त्योहारों के अवसर पर पुनर्वास गृह में धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने एवं उनकी उम्र एवं शारिरीक क्षमता को मध्यनजर रखते हुए योग एवं इन्डोर गेम्स की व्यवस्था करने के संबंध में निर्देश प्रदान किये गयें।

महवा में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय, मुनापुरा, खोचपुरी में 133 केवी जीएसएस, पहाड़ी सिद्ध बाबा आश्रम पर ऐनिकट सहित अन्य विकास योजनाओं की बजट में हुई घोषणा

शफीक अली

महवा (रॉयल पत्रिका) । महवा विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजेंद्र मीणा के प्रयासों सेबजट 2026-27 में विधानसभा क्षेत्र महुवा को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी गई है विधायक राजेंद्र मीणा ने महुवा विधानसभा क्षेत्र में बजट 2026 ,27 में दी गई सौगातो को लेकरप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद देते हुए बजट की सराहना की। विधायक राजेंद्र मीणा ने बताया कि महवा विधानसभा क्षेत्र के लिए

बजट 2026, 27 मेंग्राम पंचायत मुनापुरा एवं खोंचपूरी में 33/11 के.वी. जीएसएस की घोषणा, महवा में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय की स्थापना तथा पंचायत समिति मनोहरपुर खेड़ला, में स्थित पहाड़ी (सिद्ध बाबा) एनिकट निर्माण क्षेत्र में एनीकेटों के निर्माण एवं जीर्णोद्वार हेतु करोड़ों रुपये की स्वीकृति दी गई है जिससे महवा विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान करेगी। विधायक राजेंद्र मीणा ने कहा किडबल इंजन की भाजपा सरकार में राजस्थान निरंतर विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर गांव तक प्रगति की रोशनी पहुंच रही है। आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध राजस्थान की दिशा में निरंतर अग्रसर - आपणो अग्रणी राजस्थान हो रहा है।

राजकीय विद्यालय में नशा मुक्ति कार्यशाला आयोजित

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। जिला कलक्टर डॉ. मंजू एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के नेतृत्व में नशे के खिलाफ मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 के लिए जागरूकता कार्यशाला महाराजा अग्रसेन विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे, सोशल मीडिया की लत, ऑनलाइन गेमिंग और नकारात्मक सोच जैसे खतरों से अवगत कराते हुए उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से विक्रम ज्याणी ने कहा कि आज की पीढ़ी देश का भविष्य है, लेकिन यही पीढ़ी यदि नशे और गलत आदतों की गिरफ्त में आ गई तो आने वाला कल अंधकारमय हो सकता है। नशा केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि सोच रिश्तों और सपनों को भी खोखला कर देता है। विद्यार्थियों से आह्वान किया गया कि वे मोबाइल और इंटरनेट के गुलाम न बनें, बल्कि उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का साधन बनाएं। विद्यालय प्रशासन की ओर से प्रधानाचार्य अनामिका दाधीच ने कहा कि ऐसी कार्यशाला केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों को सुरक्षित, संस्कारित और आत्मनिर्भर बनाने का एक संकल्प है । कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहने और एक सकारात्मक समाज के निर्माण में योगदान देने की शपथ ली। पुलिस कांस्टेबल प्रवीण कुमार ने साइबर सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के लिए युवाओं को जागरूक किया।

वित्त मंत्री दियाकुमारी द्वारा प्रस्तुत बजट से राजस्थान का होगा सर्वांगीण विकास - मानसिंह गुर्जर

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। प्रदेश की वित्त मंत्री दियाकुमारी द्वारा बुधवार को प्रस्तुत किया गया तीसरा बजट राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जिला प्रवक्ता सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि आज प्रस्तुत किए गए ऐतिहासिक बजट को भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर ने सराहा है, जिलाध्यक्ष ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक बजट पर सम्पूर्ण प्रदेश के विकास पर ध्यान दिया गया है, प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विकसित राजस्थान के निर्माण का बजट है, बजट में सभी

वर्गों का ध्यान रखा गया है, यह सर्व समावेशी और सर्व हितैषी बजट है। बजट किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और गरीब के उत्थान को समर्पित बजट है, बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया गया है, बजट में 6500 गांवों तक हर घर पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में महिलाओं को अब 1.50 लाख तक के लोन का प्रावधान किया गया है, वही जिन मरीजों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हें भी राजस्थान में फ्री इलाज मिलेगा, जलदाय विभाग में 3000 संविदाकर्मियों की भर्ती की जावेगी, जबकि 5000 होमगार्ड की भी भर्ती की जावेगी, जिलाध्यक्ष मानसिंह ने बताया कि बजट में राजकोषीय घाटे को कम करते हुए एक लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सप्रीचर का प्रावधान किया गया है।

वेयरहाउस में मजदूर को काम से रोके जाने का आरोप, लेबर यूनियन ने दी धरने की चेतावनी

निशान सतराना

श्रीगंगानगर/पदमपुर (रॉयल पत्रिका)। भगत सिंह पल्लेदार लेबर यूनियन श्रीगंगानगर की ओर से उप तहसीलदार रिडमलसर को एक ज्ञापन सौंपकर वेयरहाउस में मजदूर को कार्य दिलाने की मांग की गई है। यूनियन का आरोप है कि रिडमलसर तहसील के निवासी मजदूर को वेयरहाउस ठेकेदार द्वारा जानबूझकर कार्य से वंचित किया जा रहा है, जिससे मजदूर और उसके परिवार के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। यूनियन जिलाअध्यक्ष अवतार सिंह ने बताया कि संबंधित मजदूर यूनियन का सक्रिय सदस्य है और पूर्व में वेयरहाउस में लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य करता रहा है, लेकिन वर्तमान में ठेकेदार द्वारा उसे बिना किसी ठोस

कारण के काम पर नहीं लगाया जा रहा। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि मजदूर को शीघ्र कार्य नहीं दिया गया, तो 13 फरवरी 2026 को सज्जनवाला वेयरहाउस व भगवानगढ़ वेयरहाउस सहित शंकर सीड्स, सहारण वेयरहाउस और सोरभ ट्रेडिंग कंपनी के बाहर शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा। यूनियन ने यह भी स्पष्ट किया कि धरने के दौरान किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। लेबर यूनियन ने प्रशासन से मांग की है कि ठेकेदार से वार्ता कर मजदूर को तुरंत काम दिलाया जाए तथा संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि मजदूर परिवार की रोज़ी-रोटी सुरक्षित रह सके। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अवतार सिंह, युवा नेता युवराज सिंह, कुलविंदर सिंह, देवेंद्र सिंह, मनजीत सिंह, मेजर सिंह समेत मौजूद रहे।

सवाई माधोपुर में पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस आयोजित

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। भाजपा जिला कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी में संगठन के स्तंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर "समर्पण दिवस" कार्यक्रम का आयोजन भाजपा जिला कार्यालय पर किया गया। मंडल प्रवक्ता ओम शर्मा ने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष मानसिंह गुर्जर के निर्देशानुसार भाजपा जिला कार्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उपस्थित नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों व आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। पूर्व यूआईटी चेयरमैन एवं महामंत्री जगदीश अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांत के माध्यम से भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। उनका जीवन राष्ट्रसेवा, सादगी और समर्पण का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता उनके बताए मार्ग पर चलकर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य करने का संकल्प दोहराएं। इसी क्रम में जिला उपाध्यक्ष पं.लालचंद गौतम ने कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के त्याग और बलिदान के बारे में बताया। वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संगठनात्मक कौशल, वैचारिक दृढ़ता और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। समर्पण दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने समाज सेवा और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष हरि ओम गर्ग, जिला प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा, विस्तारक गौरव फौजदार, बजरिया मंडल अध्यक्ष रितेश भारद्वाज, शहर मंडल अध्यक्ष कपिल जैन, महामंत्री केशव शर्मा, रामपाल बालोत, मुकेश शर्मा, नील कमल जैन, कृष्णा मथुरिया, राजेश मीणा, शुभम भारद्वाज, सीताराम शुक्ला, सावित्री शर्मा, मीरा मीणा और कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बजट ने जनता की उम्मीद पर पानी फेरा - भूराराम

पाली (रॉयल पत्रिका)। प्रदेश की जनता सरकार के बजट का इंतजार करती है लेकिन पर्ची से चलने वाली वर्तमान सरकार का बजट निराशाजनक साबित हुआ। भविष्य (2047) के विजन की बाते करना आसान है लेकिन जो क्रियान्वित ना हो सके वो सपने क्या काम के वर्तमान में सरकार शिक्षा, रोज़गार, चिकित्सा, पेयजल, सड़के आदि में क्या दिया वो मायने रखता हैं। सरकार रोज़गार उपलब्ध कराती तो जो मेंटल हॉस्पिटलओ की बाते आज वितमंत्री ने कही ज़रूरत नहीं पड़ती केंद्र के बजट के बाद राज्य सरकार के बजट ने जनता की भावनाओं पर पानी फेर दिया।

बजट पूरी तरह भार्मक है इसमें किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं किया गया है- हसन रियाज चिश्ती

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय से सामाजिक कार्यकर्ता हसन रियाज चिश्ती ने कहा बजट पूरी तरह भ्रामक है। इसमें किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं किया गया है अगर चूरू के बारे में बात करें तो चूरू को सिर्फ झींगा पालन में बिजली पर सब्सिडी देने की बात है। चूरू जैसे बड़े जिले में किसी भी प्रकार का विकास कार्य किसी भी प्रकार का शैक्षणिक कार्य सरकार को नजर नहीं आया। छात्रों के लिए महिलाओं के लिए बजट के अंदर कुछ भी नहीं है।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा को किया सम्मानित

चूरू (रॉयल पत्रिका)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बुधवार को जयपुर में राज्य प्रशिक्षण केंद्र, जगतपुरा में आयोजित राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा को सम्मानित किया। जिला कलक्टर सुराणा को स्काउट गाइड सेवाओं के उन्नयन व प्रोत्साहन के लिए "धन्यवाद बैज" से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ समारोह के दौरान चूरू जिले के कुल 357 स्काउट-गाइड्स को राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, इनमें 246 स्काउट, 77 गाइड, 21 रोवर एवं 13 रेंजर शामिल हैं। बड़ी संख्या में पुरस्कार प्राप्त कर चूरू जिले ने प्रदेश स्तर पर अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की है। इसी के साथ अवार्ड रैली में भी चूरू जिले का उत्साहपूर्ण प्रतिनिधित्व रहा, जिसमें चार स्काउट, दो गाइड, एक रोवर तथा एक रेंजर ने भाग लेकर जिले का मान बढ़ाया है। स्काउट महिपाल सिंह तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह उपलब्धि जिले के स्काउट-गाइड्स की कड़ी मेहनत, अनुशासन, सेवा भावना एवं नेतृत्व क्षमता का परिणाम है। यह सफलता चूरू जिले के स्काउट-गाइड संगठन के समर्पित प्रयासों और निरंतर प्रशिक्षण का प्रतिफल है, जिससे जिले का नाम प्रदेश स्तर पर गौरवान्वित हुआ है।

पाली जिले को मिली विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात, सैकड़ों करोड़ के कार्य स्वीकृत

मोहम्मद यासीन

पाली (रॉयल पत्रिका)। जिले के समग्र विकास को गति देने के लिए सरकार द्वारा सड़कों, पुलों, बिजली, जल निकासी, सीवरेज, स्वास्थ्य, शिक्षा और धार्मिक स्थलों के विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। भाजपा प्रवक्ता त्रिलोक चौधरी ने बताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी और विकास को नई दिशा मिलेगी। स्वीकृत कार्यों में आमलिया भिमाना से टण्डी बेरी सड़क निर्माण हेतु 13 करोड़ रुपये, जैतारण से बिलाड़ा सड़क के लिए 25 करोड़ रुपये, गुड़ा जेतसिंह नदी पर पुलिया निर्माण हेतु 5.50 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके साथ ही रोहट से आहोर हाईवे के लिए 550 करोड़ रुपये की बड़ी परियोजना स्वीकृत की गई है। सुमेरपुर में 33 केवी जीएसएस, सुमेरपुर में सीवरेज द्वितीय चरण की डीपीआर के लिए 30 लाख रुपये, सांडिया तालाब की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं पाली में 15 एमएलडी नए एसटीपी प्लांट एवं पुराने प्लांट के अपग्रेडेशन हेतु 43 करोड़ रुपये तथा ड्रेनेज सुधार के लिए 40 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डीएमआईसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा के क्षेत्र में जैतारण में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु खिंवाड़ा रानी चिकित्सा केंद्र का क्रमोन्नयन किया जाएगा। इसके अलावा कृष्ण मूर्ति धाम एवं मकरमंडी माताजी मंदिर विकास कार्य, जवाई केनाल की रिपेयरिंग हेतु 25 करोड़ रुपये, तथा सिणगारी, सरदार समंदर से मारवाड़ क्षेत्र से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। इन सभी परियोजनाओं से पाली जिले में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आमजन को सीधा लाभ पहुंचेगा।

राज्य बजट पंचायत व नगर पालिका चुनावों के लिए मात्र लोक-लुभावन दर्शाता है - एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति

चुरु (रॉयल पत्रिका)। जिला प्रवक्ता कांग्रेस एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने कहा कि ये बजट कागजी लग रहा है। पंचायत व नगर पालिका चुनाव को देखते हुए लोक लुभावन दर्शाता है हर घर कों पेयजल के लिए जोड़ना बस कागजो तक ही सिमित है। पुर्व बजट में की गई घोषणाओं को की पुर्ति तो दुर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। राज्य बजट में उच्च शिक्षण संस्थाओं और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रिक्त पदों को भरने की कोई अलग से घोषणा नहीं हुई है पशु-चिकित्सक और चिकित्सा लक्ष्यों की नवीन घोषणाऐ किसी भी क्षेत्र के लिए अलग से नहीं हुई है। आंगनबाड़ी,होम गार्ड, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वर्षों से कार्यरत मानदेय कर्मीयों का मानदेय बढ़ाने की ओर नियमित करने की बजट में व्यवस्था नहीं की है। वर्षा जल संचयन और कृषि कुंड की प्रयाप्त घोषणा नहीं हुई है डीजल पेट्रोल पर वैट कम नहीं करने की घोषणा से महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। मजदूर किसान सामान्य परिवार इस बजट घोषणा से संतुष्ट नहीं हैं।

महस्वा में ई-धरती एप बना किसानों की परेशानी, नामांतरण अटका

हनीस शेख

करौली (रॉयल पत्रिका)। करौली जिले की टोडाभीम तहसील के ग्राम महस्वा में ई-धरती एप अपडेट के बाद किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार और गैर-खातेदारों को एक ही खाते में दर्शाने के कारण जमीन बिक्री के बाद भी नामांतरण नहीं खुल पा रहा है। किसानों का कहना है कि भू-आवंटन को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसके बावजूद अब तक खातेदारी अधिकार नहीं दिए गए। नामांतरण अटकने से किसान जमीन बेचने या खरीदने में असमर्थ हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि खातेदार और गैर-खातेदारों को अलग-अलग खाता संख्या दी जाए या ई-धरती एप की जगह तहसील स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि नामांतरण की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सके।

युवाओं को बजट में उम्मीद थी बजट तो फूटा गुब्बारा निकला - अरविंद भाम्बु भामसी

मोहम्मद अली पठान

चूरू (रॉयल पत्रिका)। सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद भाम्बु भामासी ने कहा प्रदेश के युवाओ को बजट मे उम्मीद थी की रोजगार पर बल दिया जायेगा पर बजट तो फुटा गुब्बारा निकला, नौकरी दूर- दूर नजर नहीं आ रही है साथ ही चुरू जिला मरुस्थलीय जिलों मे शामिल केवल परिशिमन मे ही नजर आया बजट मे गायब कर दिया गया महसूस हुआ जो जिले की जनता के साथ छलावा लगा है साथ ही खेजड़ी सहित अन्य वृक्ष के संरक्षण हेतु निराशा हाथ लगी व चुरू जिला मुख्यालय की यातायात व्यवस्था के लिए सड़को और जयपुर रोड़ पुल के पुनः निर्माण और रिंग रोड़ निर्माण की बात केवल चुनावी जुमला ही साबित हुई है जिले के लिए हर पहलू से ये बजट छलावा और केवल आंकड़े का बजट ही नजर आया और झींगा उत्पादन के लिए घोषणा केवल मात्र ऊंट के मुँह मे जीरे जैसी महसूस हुई जो की जिले के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

ऐतिहाहिक धर्म स्तूप के पास गंदगी के ढेरों ने खोली प्रशासन की पोल, अब तो आँखें खोल !

-कम से कम ऐतिहासिक स्थलों को तो भ्रष्टाचार और गंदगी से मुक्त रखो

मोहम्मद अली पठान

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर स्थित ऐतिहाहिक धर्म स्तूप के पास लगे गंदगी के ढेर नगरपरिषद और जिला प्रशासन की पोल खोल रहे हैं। यहां स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ कागजों में ही चल रहा है। धर्म स्तूप के निकट ही इंद्रमणि पार्क है। इसके पास गली पूरी तरह से गंदगी से भरी हुई रहती है। यहां के उच्च अधिकारी केवल भाषणों में ही धर्म स्तूप का जिक्र करते हैं। वास्तव में तो उन्हें यहां फैली दुर्गंध के कारण आमजन को हो रही परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा वाले अपनी पार्टी की सरकार होने के कारण चुप हैं तो कांग्रेस वाले भी संपर्क खराब होने के डर से चुप्पी साधे बैठे हैं। उल्लेखनीय है कि धर्म स्तूप पर आजादी से पहले ध्वजारोहण करके तिरंगा फहरा दिया गया था। आज यहां सफाई तक नहीं होना बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। जागो प्रशासन जागो। कम से कम ऐतिहासिक स्थलों को तो भ्रष्टाचार गंदगी से मुक्त रखो।

आलीसर में बाबा भूधरदास महाराज का 51वां वार्षिक मेला

-कलश यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

चौमूं (रॉयल पत्रिका)। ग्राम आलीसर बस स्टैंड के पास स्थित बाबा भूधरदास दास जी महाराज का 51वां वार्षिक मेला व श्रीराम पंचकुंडीय यज्ञ महंत गंगादास महाराज व यज्ञाचार्य पं. गजानंद शास्त्री के सानिध्य में गुरुवार को आयोजित होगा। इससे पहले बुधवार को यज्ञ मंडप परिसर से सैकड़ों महिलाओं ने डीजे की धुन पर गांव के मुख्य मार्गों से कलश यात्रा निकाली। यात्रा का ग्रामीणों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मेले व यज्ञ की तैयारियों को लेकर यज्ञ मंडप पर कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित कर अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। ट्रस्ट अध्यक्ष कार्यवाहक बलदेव शर्मा, कोषाध्यक्ष विष्णुदत्त जांगिड़, राधेश्याम शर्मा, रामलाल यादव, गोपाल मीणा, प्रकाश, श्रवण बुरा, बनवारी, रामधन व कालूराम ने बताया कि 11 फरवरी की रात्रि को सत्संग का आयोजन हुआ, जबकि 12 फरवरी को प्रातः 8 बजे यज्ञ का शुभारंभ और शाम 5 बजे पूर्णाहुति होगी। मेले को लेकर गांव में खासा उत्साह है। मंदिर व यज्ञ मंडप परिसर में सजावट का कार्य तेजी से चल रहा है और पटवा बाजार सजने लगा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिजली, पानी व चिकित्सा व्यवस्था की गई है। आसपास के गांवों में भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। कलश यात्रा के दौरान पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखी।

परंपरा निभाई गई:-

कार्यकर्ताओं प्रभुनारायण यादव व बलदेव ने बताया कि मेला व श्रीराम पंचकुंडीय यज्ञ के दौरान पंचायत क्षेत्र के किसान अपने-अपने बोरिंग व कुएं बंद रखते हैं। ग्रामीणों के अनुसार पिछले 51 वर्षों से क्षेत्र में ओलावृष्टि नहीं हुई। मेले में दूर-दराज के गांवों से हजारों श्रद्धालु बाबा के धूणे पर धोक लगाकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हैं।

बारां में तीन दिवसीय पासपोर्ट कैम्प प्रारंभ

बारां । क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोटा की ओर से जिले में मोबाइल वेन के माध्यम से तीन दिवसीय पासपोर्ट कैम्प का आयोजन बुधवार से जिला कलक्ट्रेट परिसर में प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कोटा यशवंत माठे, एडीएम भंवरलाल जनागल और एसडीएम विश्वजीत सिंह ने दीप प्रज्वलन कर मोबाइल कैम्प का शुभारंभ किया।

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी माठे ने बताया के विदेश मंत्रालय की ओर से पासपोर्ट सेवा आपके द्वार योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके द्वारा मोबाइल पासपोर्ट वैन के माध्यम से बारां जिले एवं आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को अपने स्थानीय क्षेत्र में ही पासपोर्ट बनवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उनके समय एवं संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी। माठे ने बताया के यह कैम्प 11 से 13 फरवरी तक कलक्ट्रेट परिसर में आयोजित किया जा रहा है तथा प्रतिदिन 40 पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि आवेदकों की मांग को देखकर यह कैम्प प्रतिमाह आयोजित किया जा सकता है। माठे ने यह भी कहा के पासपोर्ट कार्यालय कोटा में अब तक 2 लाख पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं जिसमें करीब 54000 ई- पासपोर्ट भी हैं और निरंतर बेहतर सेवा के प्रति वचनबद्ध हैं। एडीएम जनागल और एसडीएम सिंह ने माठे और उनकी टीम का धन्यवाद दिया और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया।

राजस्थान बजट ऐतिहासिक, हर वर्ग का रखा गया ध्यान - संगठन मंत्री जसकरण सिंह सरा

विनोद सोखल

श्रीगंगानगर (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर श्रीगंगानगर में संगठन मंत्री जसकरण सिंह सरा ने इसे ऐतिहासिक और सर्वस्पर्शी बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसमें समाज के हर वर्ग की जरूरतों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया है। सरा ने कहा कि किसानों के हित में सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, बिजली आपूर्ति में सुधार, कृषि आधारित योजनाओं को बढ़ावा और फसल सुरक्षा संबंधी प्रावधान सरकार की किसान हितैषी सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं से प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, विभिन्न विभागों में भर्तियों की घोषणा तथा कौशल विकास योजनाओं को उन्होंने बजट की प्रमुख उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं में विस्तार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा नए अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के विकास को भी सरा ने सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए प्रावधान प्रदेश के भविष्य को मजबूत करेंगे। संगठन मंत्री ने कहा कि सड़क, पानी, बिजली और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट विकासोन्मुख, संतुलित और दूरदर्शी है। अंत में जसकरण सिंह सरा ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट आमजन की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल, सूरतगढ़ की उपेक्षा से जनता में आक्रोश जिला

-कॉलेज, नहर खाले सहित प्रमुख मांगें बजट में गायब - विधायक डूंगर राम गेदर

विनोद सोखल

सूरतगढ़ (रॉयल पत्रिका)। प्रदेश में डबल इंजन सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत नजर आ रही है। हाल ही में प्रस्तुत बजट में प्रदेश के कई क्षेत्रों की महत्वपूर्ण मांगों की अनदेखी की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि विकास के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। विशेष रूप से सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के साथ इस बजट में खुली उपेक्षा की गई है। लंबे समय से सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। राजियासर, जैतसर व पालीवाला में कॉलेज और सूरतगढ़ में महिला कॉलेज की स्वीकृति नहीं दी गई। राजकीय महाविद्यालय में पीजी की नई संकाय शुरू करने की मांग भी अनसुनी कर दी गई।

किसानों की जीवनरेखा माने जाने वाले नहर के खालों की मांग को भी दरकिनार कर दिया गया, जिससे साफ है कि सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। इसके अलावा उपतहसील राजियासर और जैतसर को तहसील का दर्जा देने की वर्षों पुरानी मांग पर भी कोई घोषणा नहीं की गई। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने को लेकर भी बजट में कोई ठोस प्रावधान नजर नहीं आया। यह बजट प्रदेश व सूरतगढ़ क्षेत्र के लिए निराशाजनक साबित हुआ है। जनता को उम्मीद थी कि डबल इंजन सरकार विकास की रफ्तार तेज करेगी, लेकिन यह बजट उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया।

मदरसा रोशन इस्लामिया लिलबनात में 14 आलिमा और 25 लड़कियां बनी कारियां, 6 लड़कों ने किया कुरआन मुकम्मल

जोधपुर (रॉयल पत्रिका)। क़ौम अब्बासियान के अधीन संचालित 'मदरसा रोशन इस्लामिया लिलबनात' उदयमंदिर आसन में हर साल होने वाले 'जश्ने खत्मे बुखारी शरीफ, रिदा -ए- आलमीय्यत और किराअत' का बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। रोशन नूरी मस्जिद के पेश इमाम और मदरसे के मोहतमिम मौलाना इमरान मिस्बाही ने जानकारी दी कि मदरसे में पढ़ने वाली सैकड़ों बच्चियों में से इस साल 14 बच्चियां आलिमा और 25 बच्चियां कारियां बनी है। साथ ही रोशन नूरी मस्जिद में पढ़ने वाले 6 लड़कों ने नाज़रा कुरआन मुकम्मल किया। इन्हें सर्टिफिकेट, दस्तार व उपहार देकर सम्मानित किया गया। उन्होने कहा कि हमारे मदरसे में जोधपुर के विभिन्न इलाकों से आई छात्राएं निःशुल्क कुरआन सीखने के साथ-साथ उसका बेहतरीन आवाज में उच्चारण और हमारे नबी मुहम्मद सल्ललाहो अलैहेवसल्लम की जिंदगी जिसे हदीस कहा जाता है का लाइब्रेरी में अध्ययन भी करती है। उत्तराखंड के हाफिजों कारी मौलाना हाशमी काशीपुरी ने बतौर मुख्य वक्ता तालिम के विषय पर तकरीर करते हुए कहां की एकमात्र शिक्षा ही है जो हमें सही और गलत का भेद समझाती है। हमें लड़कों के साथ लड़कियों को भी सांसारिक, तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ इस्लामिक आधारभूत शिक्षा देनी होगी तभी सही मायनों में हम घर, समाज और मुल्क में अपनी सम्पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह कर पाएंगे। इस मौके पर बतौर विशिष्ठ अतिथि उत्तराखंड काशीपुर के मुफ्ती फैजान मंजरी ने स्टूडेंट्स सहित अन्य सभी को खत्मे बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का सामूहिक रूप से उच्चारण कराया। बच्चों सहित साल भर सराहनीय सेवाएं देने टीचर्स की हौंसला अफजाई के इस वार्षिक समारोह में क़ौम अब्बासियान के अध्यक्ष अब्दुल रशीद भाटी, सचिव मास्टर निजामुद्दीन सोलंकी, कोषाध्यक्ष मुनीर खां चौहान, सहसचिव जाकिर हुसैन मुनीमजी, सरपरस्त हाजी यासीन उस्ताद बेलिम, ईदू खां रेवासा, पार्षद शेर मोहम्मद, मदरसा प्रभारी लाडू भाटी, मदरसा सह प्रभारी अली मोहम्मद बेलिम, उपाध्यक्ष सिराजुद्दीन बबलू भाई, अनवर पंवार, निजामुद्दीन भाटी, अकरम भाटी, नगर निगम सहायक गुलाम मोहम्मद, पंचपोता प्रभारी सिकंदर पंवार, सदस्य जाबिर मास्टर, जाकिर हुसैन, बैतुलमाल प्रभारी मुस्तकीम अब्बासी व शहर के कई गणमान्य लोग, क़ौम अब्बासियान से जुड़े सदस्यगण, सरपरस्त, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं एवं बच्चे मौजूद रहें। संचालन मास्टर हसनैन ने किया। धन्यवाद क़ौम अध्यक्ष अब्दुल रशीद अब्बासी ने दिया।

कृतिका कामरा और गौरव कपूर मार्च 2026 में रचाएंगे शादी

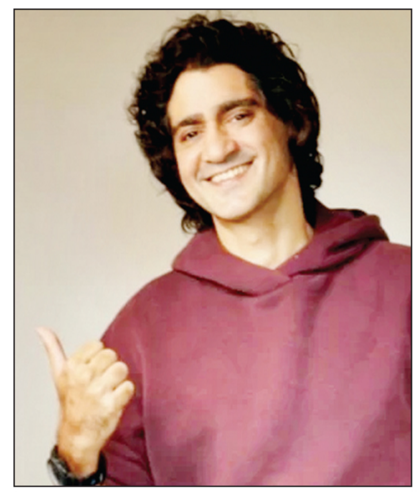

एक्ट्रेस कृतिका कामरा और गौरव कपूर को लेकर चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही हैं, क्योंकि रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने के बाद से ही यह कपल सुर्खियों में बना हुआ है पॉपुलर एक्ट्रेस कृतिका कामरा और गौरव कपूर ने पिछले साल दिसंबर में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दोनों मार्च-अप्रैल 2026 के बीच शादी के बंधन में बंध सकते हैं, जिससे फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है. हालांकि, अब तक शादी को लेकर कपल की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस कृतिका कामरा जल्द ही खुद से सात साल बड़े एक्टर और क्रिकेट प्रेजेंटर गौरव कपूर के साथ शादी के बंधन में बंध सकती हैं। बताया जा रहा है कि यह शादी मुंबई में मार्च के अंत या अप्रैल 2026 की शुरुआत में हो सकती है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि समारोह पूरी तरह प्राइवेट रहेगा, जिसमें सिर्फ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल होंगे। हालांकि, अब तक शादी की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही कृतिका कामरा या गौरव कपूर की ओर से इस पर कोई बयान सामने आया है। दिसंबर 2025 को कृतिका कामरा ने इंस्टाग्राम पर गौरव कपूर के साथ अपनी ब्रेकफास्ट डेट की तस्वीरें शेयर कीं इस पोस्ट ने उनके रिश्ते को कन्फर्म किया. बाद में एक इंटरव्यू में कृतिका ने भी गौरव को डेट करने की बात मानी। कृतिका कामरा एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री हैं, जो टेलीविजन और फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। कृतिका कामरा पहली बार 2007 में इंडियन टेलीविज़न पर मशहूर हुई और रोमांटिक ड्रामा में अपने रोल के लिए उन्हें बहुत पहचान मिली। 2010 के आखिर तक, उन्होंने डेली सोप से हटकर ज़्यादा बारीक फ़िल्म और डिजिटल प्रोजेक्ट्स में काम करना शुरू कर दिया था, और 'हश हश', 'बंबई मेरी जान' और 'भीड़' जैसे टाइटल्स में नजर आई।

क्या रणबीर कपूर की 'रामायण' में 'विभीषण' का किरदार निभाएंगे विजय सेतुपति? एक्टर ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच

साउथ एक्टर विजय सेतुपति ने अपनी दमदार अदाकारी के दम पर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है. आज वे टॉप पैन इंडिया स्टार्स की लिस्ट में शामिल हैं और हर फिल्म निर्माता और अभिनेता उनके साथ काम करना चाहता है। वहीं रूमर्स फैले हुए हैं कि विजय सेतुपति की रणबीर कपूर की 'रामायण' में एंट्री हुई है। वहीं अब इन सब अफवाहों पर खुद एक्टर ने चुप्पी तोड़ी है और सारा सच बताया है। दरअसल मूवीज़ सिंगापुर की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' के निर्माता विजय सेतुपति का को फिल्म में विभीषण की भूमिका में लेने की सोच रहे हैं। हिंदू महाकाव्य रामायण में विभीषण लंका के राजा रावण के छोटे भाई हैं। विजय सेतुपति ने अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होने की अफवाहों को खारिज कर दिया है। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह 'रामायण' का हिस्सा नहीं हैं।अफवाहों से हैरान होकर उन्होंने कहा, 'नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूं. मुझे नहीं पता कि ये अफवाहें कहां से आ रही हैं। ' नितेश तिवारी निर्देशित 'रामायण' हिंदू एपिक पर आधारित फिल्म है. इस अपकमिंग फिल्म में रणबीर कपूर भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं साई पल्लवी देवी लक्ष्मी के अवतार सीता की भूमिका में नजर आएंगी।

दिशा पाटनी के ये रेड लुक, रोमांटिक डेट के लिए परफेक्ट है ये आउटफिट

वैलेंटाइन डे के मौके पर दिशा पाटनी के रेड आउटफिट्स हर किसी का दिल जीत सकते हैं। सैटिन स्ट्रैप शोल्डर ड्रेस से लेकर सिल्क काउल नेक तक हर लुक अलग-अलग मौके के लिए परफेक्ट है। वैलेंटाइन डे प्यार जताने का दिन है और इस दिन रेड आउटफिट की अपनी ही खास पहचान होती है। अगर आप इस खास मौके पर कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं जिससे नजरें आप पर ही टिक जाएं तो दिशा पाटनी के ये रेड लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं। चाहे डिनर डेट हो नाइट पार्टी या फिर पार्टनर के साथ रोमांटिक आउटिंग दिशा के ये आउटफिट्स आपको कंफर्ट के साथ स्टाइल और कॉन्फिडेंस भी देंगे वैलेंटाइन डे पर अगर रेड कलर की बात न हो तो बात अधूरी लगती है। इस खास दिन पर दिशा पाटनी के रेड आउटफिट्स किसी भी रोमांटिक डेट को और भी खास बना सकते हैं। चाहे डिनर डेट हो, नाइट पार्टी या सिर्फ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम दिशा के ये रेड लुक्स हर मौके के लिए परफेक्ट हैं। वैलेंटाइन डे पर अगर रेड कलर की बात न हो तो बात अधूरी लगती है। इस खास दिन पर दिशा पाटनी के रेड आउटफिट्स किसी भी रोमांटिक डेट को और भी खास बना सकते हैं। चाहे डिनर डेट हो, नाइट पार्टी या सिर्फ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम दिशा के ये रेड लुक्स हर मौके के लिए परफेक्ट हैं।

स्क्रिप्ट पर भरोसा अब भी बरकरार सोशल मीडिया से फर्क नहीं पड़ता

बरुण सोबती

एक्टर बरुण सोबती की वेब सीरीज 'कोहरा' का दूसरा सीजन 11 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है। इस बीच उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में बदलाव बहुत आए हैं, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट की ताकत पर उनका विश्वास बरकरार है। सोशल मीडिया और डिजिटल दौर में भी वे काम की क्वालिटी पर फोकस करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 'दुनिया बहुत बदल गई है और सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन मेरा नजरिया वही है। मैं शुरू से स्क्रिप्ट पर भरोसा करता था और आज भी करता हूं। पहले अच्छी स्क्रिप्ट्स कम मिलती थीं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे मुझे मिल रही हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।' प्रासंगिक बने रहने के बारे में बरुण ने खुद की जागरूकता और पर जोर दिया। उन्होंने कहा,'प्रासंगिक रहने के लिए आपको अपनी काबिलियत का इस्तेमाल जिंदगी भर करना होगा। खुद की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। बल्कि यह समझना जरूरी है कि आप कहां सबसे अच्छे फिट होते हैं और आपका टैलेंट कहां सबसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। अगर यह नहीं पता तो किसी भी काम का मतलब नहीं। ' बरुण फिलहाल अपनी वेब सीरीज 'कोहरा' के दूसरे सीजन की तैयारी में जुटे हैं।

अनुपम खेर ने अपने नाम से बने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर आगाह किया

वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर ने उनके नाम से बनाए गए कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर अपने प्रशंसकों और फॉलोअर्स को सतर्क किया है और उनसे ऐसे प्रोफाइल से आने वाले किसी भी अनुरोध को अनदेखा करने की अपील की है। खेर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर उनकी तस्वीरों एवं वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं और अन्य उपयोगकर्ताओं को संदेश एवं अनुरोध भेज रहे हैं। वीडियो में खेर यह कहते सुनाई देते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों (8230), उन्होंने कहा, मेरा ऐसा कोई अकाउंट नहीं है। कृपया उन्हें नजरअंदाज करें।

चेक बाउंस मामले में जेल गए राजपाल यादव की मदद के लिए सोनू सूद ने बढ़ाया हाथ

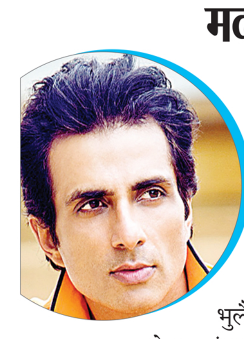

अभिनेता सोनू सूद ने चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल प्राधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले कॉमेडियन राजपाल यादव की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और उन्हें एक फिल्म में भूमिका के साथ अग्रिम राशि प्रदान करने की पेशकश की है। सूद ने फिल्म निर्माताओं और फिल्म उद्योग से जुड़े अन्य लोगों से भी अपील की कि वे इस संकट की घड़ी में अभिनेता कॉमेडियन राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आएं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) से स्नातक अभिनेता राजपाल यादव फिल्म मुझसे शादी करोगी , वक्त , फिर हेरा फेरी , पार्टनर , भूल भुलैया , हंगामा और चुप चुप के में अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं। अभिनेता द्वारा चेक बाउंस मामले में बकाया के भुगतान के लिए और समय मांगे जाने की अर्जी को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया।

'प्लेबॉय' में फोटोशूट से मिली शोहरत : शर्लिन चोपड़ा

हिंदी सिनेमा में जहां सशक्त मुख्य भूमिकाओं के लिए अभिनेत्रियों की अहमियत बनी रही है, वहीं कुछ बोल्ड अभिनेत्रियों और मॉडलों ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है। इन कलाकारों ने पारंपरिक अभिनय से इतर अपनी बेबाक छवि और बोल्ड प्रजेंटेशन के जरिए दर्शकों के बीच खास जगह बनाई। आज भी वह ओटीटी मंचों पर सक्रिय हैं और अपने बोल्ड दृश्यों के कारण चर्चा में रहती हैं। मीडिया में भी उनकी मौजूदगी लगातार बनी रहती है, जिससे वह सुर्खियों में रहती हैं। कम ही लोग जानते हैं कि शर्लिन चोपड़ा को असली पहचान फिल्मों के जरिए नहीं, बल्कि मैग्जीन जगत से मिली। एक प्रतिष्ठित मैग्जीन में उनकी बोल्ड फोटोज ने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई, जिसके बाद वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी चर्चा का विषय बनीं। यही पहचान आगे चलकर उनके करियर की दिशा तय करने में भी अहम साबित हुई। शर्लिन को मॉडल बनने का शौक बचपन से था और यही वजह रही कि मात्र 15 साल की उम्र में अभिनेत्री ने मिस आंध्र का खिताब जीता था। मॉडलिंग के बाद अभिनेत्री फिल्मों में काम करने के लिए कई ऑडिशन दिए और साल 2002 में उन्हें तमिल फिल्म वेंडी मब्बू' में काम किया था, जो एरोटिक फिल्म थी। उसी साल, उन्होंने एक तमिल फिल्म 'यूनिवर्सिटी' और एक अंग्रेजी फिल्म 'बीपर' में भी अभिनय किया। तीनों फिल्में पर्दे पर रिलीज हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अपना बजट भी नहीं निकाल पाई।बॉलीवुड में शर्लिन ने एंट्री 2005 में आई फिल्म 'टाइम पास' से की थी। जिसके बाद 'दोस्तीः फ्रेंड्स फॉरएवर', जवानी दीवानीः ए यूथफुल जॉयराइड', 'नॉटी बॉय','गेम','रकीब', 'रेड स्वस्तिक',और 'दिल बोले हड़िप्पा! जैसी फिल्मों में काम किया। शर्लिन की फिल्में कब आई और कब चली गई, किसी को पता नहीं चला, लेकिन साल 2012 में ग्लोबल लेवल पर शर्लिन के नाम की सुनामी आ गई। अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा उस समय सुर्खियों में आई, जब वह प्लेबॉय मैग्जीन के लिए बिना कपड़ों के फोटो शूट कराने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। हालांकि, इस मामले में विवाद तब खड़ा हुआ, जब प्लेबॉय मैग्जीन ने यह कहकर इनकार किया कि उनकी शर्लिन के साथ किसी तरह की प्रत्यक्ष मुलाकात हुई थी। इसके बावजूद बाद में अभिनेत्री का डिजिटल फोटो शूट जारी किया गया।

(साभार एजेंसी)

सचिन ने अंडर-19 कप्तान आयुष को अपनी टेस्ट जर्सी दी

बोले- मेहनत करते रहो, लोगों के बहकावे में मत आओ

मुंबई (एजेंसी)। अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद भारत के कप्तान आयुष म्हात्रे जिम्बाब्वे से भारत लौटने के बाद सचिन तेंदुलकर से मिले। इससे पहले, मुंबई एयरपोर्ट पर कप्तान आयुष म्हात्रे समेत सभी खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत हुआ। म्हात्रे का पूरा परिवार उनके माता-पिता उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे।

सचिन के घर पहुंचे म्हात्रे- म्हात्रे भारत वापस लौटने के बाद सोमवार को महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के घर पहुंचे। आयुष म्हात्रे को सचिन तेंदुलकर से एक खास तोहफा मिला। तोहफा में सचिन ने अपनी टेस्ट जर्सी भेंट की,साथ ही उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ एक संदेश भी दिया।

वीडियो में सचिन ने म्हात्रे से कहा, यह वही जर्सी थी जिसे उन्होंने अपनी अंतिम टेस्ट सीरीज में पहना था। वो आगे कहते है, लगातार मेहनत करते रहो। ध्यान केंद्रित रखो। लोगों के बहकावे में मत आओ। अभ्यास करते रहो। एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है। चाहे जो भी हो, ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत होंगी।

म्हात्रे ने मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया- म्हात्रे ने मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए अपनी खुशी व्यक्त की। लिखा, मैं आपको स्क्रीन पर देखते हुए बड़ा हुआ। आज मैं आपके घर पर खड़ा हूं और आपकी यात्रा का एक हिस्सा अपने हाथों में थामे हुए हूं। इस सम्मान के लिए आपका धन्यवाद, सर। मैं इसे उसी आदर और सम्मान के साथ संभालकर रखूंगा, जैसे आपने सालों तक भारतीय क्रिकेट को सम्मान के साथ आगे बढ़ाया।

टीम इंडिया छठी बार टूर्नामेंट की चैंपियन बनी- अंडर-19 क्रिकेट में दुनिया की सबसे सफल टीम भारत फिर से वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे में खेला गया अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया। इसके साथ ही टीम इंडिया रिकॉर्ड छठी बार टूर्नामेंट की चैंपियन बनी।

टी-20 वर्ल्डकप

भारतीय खिलाड़ी परिवार के साथ नहीं रहेंगे

नईदिल्ली (एजेंसी)। टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान भारतीय क्रिकेटर अपने परिवार (पत्नियां और मंगेतर) के साथ नहीं रह सकेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम मैनेजमेंट की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें खिलाड़ियों की पत्नियों और मंगेतरों को टीम होटल में साथ ठहराने की अनुमति मांगी गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई

ने स्पष्ट किया है कि टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के परिवार को टीम के साथ ठहरने की इजाजत नहीं है। हालांकि, यदि कोई खिलाड़ी चाहे तो अपने परिवार के लिए होटल में अलग ठहरने की व्यवस्था खुद कर सकता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी उसे उठानी होगी। इसके लिए बीसीसीआई की ओर से कोई इंतजाम नहीं किया जाएगा। भारत टी-20 वर्ल्ड कप का सह-मेजबान है। बीसीसीआई का मानना है कि टीम को केवल पाकिस्तान से मुकाबले के लिए श्रीलंका जाना है। ऐसे में खिलाड़ियों को परिवार के साथ रहने की जरूरत नहीं है।

भारतीय पूर्व कप्तान ने नासिर हुसैन को लताड़ा, सूर्यवंशी का दिया उदाहरण

पुरानी ताकतों को भारत का दम देखना पच नहीं रहा: गावस्कर

मुंबई, एजेंसी

टी20 विश्वकप से पहले भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर शुरू हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा आखिरकार समाप्त हो गया। पाकिस्तानी सरकार ने पीसीबी और पाकिस्तान टीम से भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच में खेलने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले एक फरवरी को पाकिस्तानी सरकार ने बांग्लादेश के समर्थन में ड्रामा करते हुए भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कारण करने का एलान किया था। नौ दिन के ड्रामे के बाद और आईसीसी के चाबुक के बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े।

जब पाकिस्तान का यह ड्रामा शुरू हुआ था, तो कुछ क्रिकेट पंडितों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अपना समर्थन दिखाया था और भारत पर सवाल उठाए थे। इनमें इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन भी शामिल हैं। अब भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने उन्हें करार जवाब देते हुए लताड़ा है। गावस्कर का कहना है कि पुरानी ताकतों को भारत का दम देखना पच नहीं रहा। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी का उदाहरण देते हुए नासिर हुसैन की जमकर खिंचाई की।

सुनील गावस्कर का पलटवार

सुनील गावस्कर ने इस टिप्पणी का सीधा नाम लिए बिना जवाब दिया। उन्होंने लिखा, 'कुछ लोग, खासकर पुरानी ताकतें, यह पचा नहीं पा रही हैं कि अब विश्व क्रिकेट का पावर सेंटर भारत है।' उन्होंने कहा कि सवाल पूछने वाले यह भूल जाते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने पाकिस्तान जाने से काफी पहले ही मना कर दिया था। तब तक शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया था और इसके बाद ही आईसीसी ने न्यूट्रल वेन्यू का इंतजाम किया था।

वैभव सूर्यवंशी वाला तंज :उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की 175 रन की विस्फोटक पारी का जिक्र करते हुए व्यंग्य किया। 'अब अगर देखें तो जो वैभव सूर्यवंशी ने किया, वही असली धौंस जमाना (बुलीइंग) है, न कि वो काल्पनिक बुलीइंग जो कुछ लोग देखते हैं।' यह टिप्पणी सीधे तौर पर उन आलोचनाओं पर वार थी, जिनमें भारत या बी सी सी आई को ताकत का गलत इस्तेमाल करने वाला बताया जा रहा था।

क्या बोले थे नासिर हुसैन?

'अगर भारत किसी टूर्नामेंट से एक महीने पहले कह देता कि हमारी सरकार हमें किसी देश में खेलने नहीं देगी, तो क्या आईसीसी उतना ही सख्त रहता? हर कोई सिर्फ एक चीज चाहता है, समानता।' नासिर ने यह भी जोड़ा कि भारत के पास पैसा है, ताकत है, लेकिन ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है।

2003 वर्ल्ड कप का उदाहरण

गावस्कर ने दोहरे मापदंड दिखाने के लिए 2003 विश्व कप की घटना याद दिलाई, जब इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में खेलने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा, 'तब कोई सुरक्षा खतरा नहीं था, फिर भी इंग्लैंड ने खेलने से इनकार कर दिया और अंक छोड़ दिए। क्या आईसीसी ने कुछ किया? नहीं।

आईसीसी वोटिंग पर भी उठाया मुद्दा

गावस्कर ने यह भी याद दिलाया कि बांग्लादेश के मामले में आईसीसी बोर्ड की वोटिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर बाकी सभी ने उनके प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया था। इसके बावजूद निशाना सिर्फ भारत पर साधा गया।

गिल, बुमराह और जडेजा को ग्रेड ए में जगह मिली, बीसीसीआई की रिटेंशन लिस्ट जारी

रोहित-कोहली ग्रेड-बी पर खिसके

मुंबई (एजेंसी)। बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को ए प्लस ग्रेड से डिमोट करके बी ग्रेड में डाल दिया है। बोर्ड ने सोमवार को 2025-26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल प्लेयर्स की लिस्ट जारी की। ए प्लस ग्रेड को समाप्त कर दिया गया है।रोहित और कोहली के साथ बुमराह और जडेजा भी पिछले साल ए प्लस ग्रेड में शामिल थे। ताजा लिस्ट में इन दोनों को ग्रेड ए में शामिल रख गया है। वहीं, टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ग्रेड ए में बरकरार रखे गए हैं। ग्रेड बी में टी-20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा 10 अन्य खिलाड़ियों को रखा गया है। ग्रेड सी में तिलक वर्मा और रिंकू सिंह समेत 17 खिलाड़ी हैं।बोर्ड ने रिटेन खिलाड़ियों को 3 ग्रेड में बांटा है। इनमें ए-बी और सी शामिल हैं। बोर्ड ने अभी तक नए ग्रेड मॉडल की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं कहा है। कुछ दिन पहले इसे बदलने की बात कही जा रही थी। पिछले साल ए प्लेस ग्रेड में शामिल प्लेयर्स को 7 करोड़ रुपए सालाना मिलते थे। वहीं, ग्रेड ए में 5 करोड़, ग्रेड बी में 3 करोड़ और ग्रेड सी में 1 करोड़ रुपए दिए जाते थे।

रोहित-कोहली को ग्रेड-ए से बाहर क्यों किया?

रोहित और कोहली अब केवल वनडे खेल रहे हैं। इस वजह से दोनों को ग्रेड बी में डाला गया है। दोनों दिग्गजों ने पिछले साल टी-20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद टी-20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था। उसके बाद मई 2024 में टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया था।

मेंस कैटेगरी में 30 खिलाड़ियों को शामिल किया

मेंस कैटेगरी में 30 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ग्रेड ए में 3, ग्रेड बी में 11 और ग्रेड सी में 17 खिलाड़ी रखे गए हैं। जबकि, विमेंस कैटेगरी में 21 नाम शामिल हैं। ए प्लस ग्रेड को समाप्त कर दिया है। इसमें शामिल बुमराह-जडेजा ग्रेड ए में रखे गए हैं। जबकि, गिल ग्रेड में बरकरार हैं। वे पिछले साल भी इसी ग्रेड में थे। पिछले साल ग्रेड ए में शामिल केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत को ग्रेड बी में डिमोट किया गया है। इसमें सूर्यकुमार, कुलदीप, यशस्वी, सुंदर और अय्यर को जगह मिली है। ये सभी पिछले साल ग्रेड बी में रखे गए थे। ग्रुप सी में तिलक, रिंकू, शिवम, सैमसन, आकाश दीप, अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, जुरेल, हर्षित राणा, चक्रवर्ती, नीतीश रेड्डी, अभिषेक शर्मा, रवि बिश्नोई और गायकवाड़ अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं।

नीदरलैंड ने नामीबिया को 7 विकेट से हराया

नईदिल्ली (एजेंसी)। नीदरलैंड ने टी-20 वर्ल्ड कप के 10वें मैच में नामीबिया पर 7 विकेट की जीत हासिल की। टीम ने ग्रुप ए के मैच में 157 रन का टारगेट 18 ओवर में 3 विकेट पर चेज कर लिया।दिल्ली के अरुण जेटली स्टडियम में नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। पहले बैटिंग करते हुए नामीबिया ने 20 ओवर में 8 विकेट

156 रन बनाए।नीदरलैंड की ओर से बास डी लीडे ने 48 बॉल पर 72 रन की पारी खेली। जबकि कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स 18 रन पर नाबाद लौटे। कॉलिन एकरमैन ने 32 और माइकल लेविट ने 28 रन बनाए।नामीबिया की ओर से निकोल लोफ्टी-ईटन ने 42, जॉन फ्राइलिनक ने 30 और जेजे स्मिट ने 15 बॉल पर 22 रन बनाए। लोगान वैन बीक और बास डी लीडे ने 2-2 विकेट लिए। आर्यन दत्त और फ्रेड क्लासन को 1-1 विकेट मिला। विलेम मायबर्ग और रूबेन ट्रम्पेलमैन रन आउट हुए।

नीदरलैंड जीत से ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल के नंबर-2 पर आया

इस जीत के साथ नीदरलैंड की टीम ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल के दूसरे स्थान पर आ गई है। टीम के पास दो मैच में एक जीत के साथ 2 अंक हैं। भारत और पाकिस्तान के पास भी 2-2 अंक हैं। भारत का नेट रन रेट नीदरलैंड से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान का नेट रन रेट कम है।

ट्रैविस हेड का दिलचस्प खुलासा

अभिषेक की गेंदबाजी का करना चाहते हैं सामना

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज़ ट्रैविस हेड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान एक दिलचस्प खुलासा किया है। सनराइजर्स हैदराबाद में उनके ओपनिंग पार्टनर रहे अभिषेक शर्मा को लेकर हेड ने कहा कि वह टूर्नामेंट में उनके खिलाफ बल्लेबाज़ी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अभिषेक उन्हें गेंदबाज़ी करें।

रैपिड-फायर राउंड में दिया मज़ेदार जवाब- आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले एक रैपिड-फायर राउंड के दौरान ट्रैविस हेड से कई सवाल पूछे गए। जब उनसे पूछा गया कि वह किस गेंदबाज़ के खिलाफ मुकाबला करना चाहते हैं, तो उन्होंने बिना झिझक अभिषेक शर्मा का नाम लिया। अभिषेक भारतीय टीम में सूर्यकुमार यादव के पास मौजूद विकल्पों में से एक हैं, हालांकि वह नियमित रूप से गेंदबाज़ी नहीं करते।

टी-20 वर्ल्डकप में भारत-पाकिस्तान मैच होगा

श्रीलंका के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद मानी शहबाज सरकार, 15 फरवरी को मुकाबला

नईदिल्ली (एजेंसी)। टी-20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। पाकिस्तान सरकार ने सोमवार रात अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की। पोस्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने फोन कर भारत के खिलाफ मैच खेलने की अपील की थी। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से मुकाबला खेलने की सिफारिश की थी।

दरअसल, बांग्लादेश को टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के विरोध में पाकिस्तान ने 1 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। हालांकि उसने टूर्नामेंट के बाकी मुकाबले खेलने पर सहमति जता दी थी।

पाकिस्तान सरकार ने कहा था- वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन भारत से नहीं

पाकिस्तान ने 1 फरवरी को घोषणा की कि वह टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करेगा। पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाने के बाद लिया। बांग्लादेश सरकार ने भारत में खेलने को लेकर सुरक्षा चिंता जताई थी। सरकार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी वर्ल्ड टी20 2026 में हिस्सा लेने की मंजूरी देती है। हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।

हमें रेवेन्यू में भारी नुकसान होगा- एसएलसी

7 फरवरी को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (एसएलसी) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) से इस मैच पर दोबारा विचार करने की अपील की थी। इसके बाद श्रीलंका क्रिकेट ने पीसीबी को मेल लिखा। इसमें कहा गया है कि भारत-पाकिस्तान मैच नहीं होने से श्रीलंका क्रिकेट को आर्थिक नुकसान होगा और टूर्नामेंट की इमेज को भी नुकसान होगा। मेल पर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी से कहा कहा, हम भारत के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं। अगर भारत-पाकिस्तान मैच नहीं होता है तो हमें रेवेन्यू में भारी नुकसान होगा।

भारतीय टीम तय समय पर श्रीलंका जाएगी

टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर बीसीसीआई सूत्रों ने साफ किया है कि भारतीय टीम तय कार्यक्रम के अनुसार ही श्रीलंका दौरे पर जाएगी। टीम 15 फरवरी से पहले श्रीलंका पहुंचेगी और आईसीसी के सभी प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करेगी। हालांकि, मैच को लेकर अंतिम फैसला मैदान पर मौजूद मैच रेफरी द्वारा ही लिया जाएगा।

डी कॉक ने धोनी की बराबरी की

टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा डिसमिसल किए, मुन्से स्कॉटलैंड के टॉप स्कोरर

नईदिल्ली (एजेंसी)। टी-20 वर्ल्ड कप में सोमवार को 3 मुकाबले में खेले गए। साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक ने टूर्नामेंट इतिहास में सबसे ज्यादा डिसमिसल करने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली। वहीं बल्लेबाजी में स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुन्से अपनी टीम के लिए टॉप स्कोरर बन गए। टूर्नामेंट के पहले मैच में स्कॉटलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इटली को 73 रन से हरा दिया। दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे ने ओमान पर 8 विकेट से आसान जीत दर्ज की। दिन के तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने कनाडा को 57 रन से मात देकर अपने अभियान की शुरुआत की।

1. टी-20 वर्ल्डकप में किसी एसोसिएट टीम ने पहली बार 200+ रन बनाए

स्कॉटलैंड ने टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में नया रिकॉर्ड बना दिया। इटली के खिलाफ कोलकाता में टीम ने 4 विकेट पर 207 रन बनाए, जो किसी भी एसोसिएट टीम का पहला 200+ स्कोर है। इससे पहले हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड यूएसए (197/3 बनाम कनाडा, 2024) के नाम था। एसोसिएट टीम यानी वे टीमें जो आईसीसी फुल मेंबर नहीं हैं।

टी-20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत- टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में स्कॉटलैंड ने रनों के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली। टीम ने इटली को 73 रन से हराया। इससे पहले उसका सबसे बड़ा जीत अंतर 2022 में आया था, जब टीम ने होबार्ट में वेस्टइंडीज को 42 रन से हराया था।

मुन्से-जोन्स की स्कॉटलैंड के लिए टी-20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट पार्टनरशिप

टी-20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड जॉर्ज मुन्से और माइकल जोन्स के नाम दर्ज हो गया है। दोनों ने ईडन गार्डन्स में पहले विकेट के लिए 126 रन जोड़े। यह टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास में स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है।इससे पहले भी मुन्से-जोन्स की जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ 90* रन की ओपनिंग साझेदारी कर चुकी है, जो लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। वहीं दूसरी बड़ी साझेदारी में मैथ्यू क्रॉस-रिची बेरिंगटन (92 रन) और मुन्से-मैकमुलेन (89 रन) शामिल हैं।

टी-20 में पहली बार जिम्बाब्वे पेसर ने 9 विकेट लिए

कोलंबो में ओमान के खिलाफ जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों ने 9 विकेट लिए। यह पहली बार है जब टी-20 इंटरनेशनल में जिम्बाब्वे के तेज बॉलर्स ने एक पारी में 9 विकेट लिए हैं। इस मैच में रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुजरबानी और ब्रैडली इवांस ने 3-3 विकेट झटके।

सरकारी कार्यक्रमों में पहले बजेगा वंदे मातरम, 3 मिनट 10 सेकेंड के राष्ट्रगीत पर खड़ा होना अनिवार्य:

-केंद्र की नई गाइडलाइन

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए जाने की खबरों के बाद इसे लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नई गाइडलाइन के तहत सरकारी और औपचारिक आयोजनों में अब वंदे मातरम को अधिक व्यवस्थित और अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। साथ ही इसके सम्मान से जुड़े प्रोटोकॉल भी स्पष्ट किए गए हैं, ताकि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति आदर और अनुशासन का संदेश मजबूत हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी स्कूलों के आयोजनों और अन्य औपचारिक समारोहों में वंदे मातरम बजाया या गाया जाएगा, और इस दौरान उपस्थित सभी लोगों का खड़ा होना जरूरी होगा। यह भी कहा गया है कि यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों शामिल हों, तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद जन गण मन प्रस्तुत किया जाएगा। इस क्रम का उद्देश्य राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान को सुनिश्चित करना बताया गया है। नई व्यवस्था के तहत वंदे मातरम का पूरा संस्करण, जो लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का बताया जा रहा है, बजाने की बात कही गई है। वंदे मातरम मूल रूप से

छह पैराग्राफ का गीत है, लेकिन लंबे समय से सार्वजनिक कार्यक्रमों में इसके केवल पहले दो पैराग्राफ ही गाए जाते रहे हैं। अब पूरे संस्करण को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। इस गीत के विस्तृत रूप में भारत माता का वर्णन देवी स्वरूप में किया गया है, जिसमें दुर्गा सहित अन्य देवियों के प्रतीकात्मक उल्लेख मिलते हैं। इसी कारण यह गीत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भावनाओं से भी जुड़ा माना जाता है। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि वंदे मातरम को कई प्रमुख सरकारी अवसरों पर बजाया जाना चाहिए। इनमें तिरंगा फहराने के कार्यक्रम, राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान के अवसर, राष्ट्र के नाम उनके संबोधन से पहले और बाद, राज्यपालों के आधिकारिक कार्यक्रमों तथा उनके भाषणों से पहले और बाद के मौके शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा पद्म पुरस्कार जैसे नागरिक सम्मान समारोहों या ऐसे कार्यक्रमों में, जहां राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हों, वहां भी वंदे मातरम को शामिल करने की बात कही गई है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सिनेमा हॉल को इन नए नियमों से बाहर रखा गया है। यानी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना या दर्शकों का खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा। यह छूट इसलिए दी गई है ताकि मनोरंजन स्थलों और औपचारिक सरकारी आयोजनों के बीच स्पष्ट अंतर बना रहे। अधिकारियों का कहना है कि इन निर्देशों का उद्देश्य किसी पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि राष्ट्रगीत के सम्मान को लेकर एक समान और स्पष्ट दिशा तय करना है। वंदे मातरम का इतिहास भी बेहद गौरवशाली रहा है। इसे प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था। बाद में यह उनके उपन्यास 'आनंदमठ' में शामिल हुआ, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। इस रचना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाने में बड़ी भूमिका निभाई। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं रहा, बल्कि आजादी की लड़ाई का प्रेरक नारा बन गया था। साल 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम को सार्वजनिक मंच से गाया था। यह क्षण ऐतिहासिक माना जाता है। उस समय सभा में मौजूद लोगों पर इसका गहरा भावनात्मक असर पड़ा था। इसके बाद यह गीत स्वतंत्रता आंदोलन की रैलियों, सभाओं और जनजागरण अभियानों का अहम हिस्सा बन गया।

दौसा में भीषण सड़क हादसा:

-शादी से लौट रहे 6 दोस्तों की मौत, जयपुर–आगरा हाईवे पर ट्रेलर से टकराई कार

दौसा । राजस्थान के दौसा जिले में जयपुर–आगरा नेशनल हाईवे पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में छह दोस्तों की जान चली गई। यह भीषण एक्सीडेंट उस समय हुआ जब सभी युवक एक शादी समारोह से लौटकर अपने घर जा रहे थे। तेज रफ्तार और कार के अनियंत्रित होने की वजह से वाहन डिवाइडर पार कर सामने से आ रहे ट्रेलर में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार युवक बुरी तरह फंस गए। हादसा कैलाई गांव के पास रात करीब 11 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार काफी तेज गति में थी। अचानक चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया और कार सीधे डिवाइडर पार करती हुई दूसरी लेन में चली गई। उसी दौरान सामने से आ रहा भारी ट्रेलर कार से टकरा गया। टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। हादसे की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे। कार ट्रेलर में बुरी तरह फंसी हुई थी, जिसे निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद कार को अलग किया गया। अंदर फंसे युवकों को बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। घायलों को पहले सिकंदरा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चार युवकों को मृत घोषित कर दिया। दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल थे,

जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद दौसा जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ दिया। दूसरे गंभीर घायल को जयपुर के एसएमएस अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। इस तरह इस हादसे में कुल छह युवकों की जान चली गई। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में ओवरस्पीड और वाहन पर नियंत्रण खोना हादसे की मुख्य वजह नजर आ रही है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने ट्रेलर चालक से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। मृतकों की पहचान और उनके परिवारों को सूचना दे दी गई है। हादसे की खबर मिलते ही परिवारों में मातम छा गया। गांव और आसपास के इलाके में भी शोक का माहौल है। बताया जा रहा है कि सभी युवक आपस में घनिष्ठ दोस्त थे और खुशी के मौके से लौटते समय यह दुखद हादसा हो गया।

देश में मौसम के दो रंग: कश्मीर-उत्तराखंड में बर्फबारी, मध्य प्रदेश-राजस्थान में पारा 30°C पार

श्रीनगर । देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिज़ाज इन दिनों काफी बदला हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कड़ाके की ठंड और बर्फबारी जारी है, तो कहीं दिन का तापमान गर्मी का एहसास कराने लगा है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए किसी भी राज्य में बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में सर्दी का असर अभी भी तेज बना हुआ है। जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई रास्ते बंद हो गए हैं। इसी बीच भारतीय सेना ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए कुपवाड़ा जिले के तंगधार इलाके में फंसी एक गर्भवती महिला का सुरक्षित रेस्क्यू किया। भारी बर्फ और खराब रास्तों के बावजूद सेना की टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थानीय लोगों ने खूब सराहना की है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। मुनस्यारी में तापमान गिरकर माइनस 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन के सबसे ठंडे दिनों में से एक माना जा रहा है। वहीं गंगोत्री में भी पारा माइनस 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बर्फ जमी होने के कारण आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं और स्थानीय प्रशासन सतर्क बना हुआ है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौसम का उल्टा रुख देखने को मिल रहा है। यहां सुबह और शाम ठंड महसूस हो रही है, लेकिन दिन में तेज धूप के कारण तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश के करीब 15 जिलों में दिन का तापमान 30°C से ऊपर दर्ज किया गया। हालांकि रात में ठंड

अभी भी कायम है। प्रदेश के 11 जिलों में न्यूनतम तापमान 10°C से नीचे रिकॉर्ड हुआ, जिससे रात और सुबह ठिठुरन बनी हुई है। राजस्थान और हरियाणा के कई इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हुई है। इससे मौसम में हल्की नमी आई और तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। हरियाणा के 13 शहरों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा माना जा रहा है। मौसम में यह उतार-चढ़ाव किसानों के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि फसलों पर इसका असर पड़ सकता है। पंजाब में भी ठंड का असर जारी है। लुधियाना और फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 16 फरवरी से फिर बारिश होने की उम्मीद है, जिससे ठंड दोबारा बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां फिलहाल मौसम साफ रहने का अनुमान है। विभाग के अनुसार बुधवार और गुरुवार को आसमान साफ रहेगा, लेकिन 13 और 16 फरवरी को पहाड़ी इलाकों में फिर से बर्फबारी हो सकती है। कुल मिलाकर देश में मौसम इन दिनों दो अलग तस्वीरें दिखा रहा है—पहाड़ों में सख्त सर्दी और बर्फ, जबकि मैदानी इलाकों में दिन में बढ़ती गर्मी का एहसास।

भारत-US ट्रेड डील अपडेट:

-दाल पर शर्त हटी, 500 अरब डॉलर खरीद की बाध्यता भी नरम

वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जारी नई फैक्ट शीट में हुए बदलावों ने भारत को बड़ी राहत दी है। अमेरिका ने हाल ही में अपडेटेड दस्तावेज जारी किया है, जिसमें कई अहम बिंदुओं की भाषा बदली गई है और कुछ मामलों को पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे साफ संकेत मिलता है कि समझौते की शर्तों को अब ज्यादा लचीले अंदाज़ में पेश किया जा रहा है। पिछले हफ्ते दोनों देशों ने ट्रेड डील का ऐलान किया था, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी कर संभावित प्रावधानों और आगे की रूपरेखा बताई थी। उस समय दस्तावेज में लिखा गया था कि भारत अमेरिकी कृषि और औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ कम या समाप्त करेगा। इसमें दाल (पल्सेस) का भी स्पष्ट उल्लेख था। चूंकि दाल भारत के किसानों और घरेलू बाजार से जुड़ा संवेदनशील विषय है, इसलिए इस बिंदु पर काफी चर्चा हुई थी। अब जारी नई फैक्ट शीट में दाल का जिक्र पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे यह माना जा रहा है

कि भारत ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की और अमेरिका ने भाषा को नरम किया है। इससे भारतीय कृषि हितों को फिलहाल सुरक्षा मिलती दिख रही है। दूसरा बड़ा बदलाव 500 अरब डॉलर की खरीद से जुड़ा है। पहले के दस्तावेज में कहा गया था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने के लिए "कमिटेड" है। अब इस शब्द को बदलकर "इरादा रखता है" कर दिया गया है। कूटनीतिक भाषा में यह बड़ा फर्क माना जाता है, क्योंकि "कमिटमेंट" बाध्यकारी संकेत देता है, जबकि "इरादा" लचीला रुख दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलावों से साफ है कि ट्रेड डील अभी प्रक्रिया में है और अंतिम शर्तें बातचीत के बाद तय होंगी। इससे दोनों देशों को बातचीत की गुंजाइश और संतुलन बनाए रखने का मौका मिलेगा।

असम में तैयार देश का सबसे लंबा भूकंपरोधी महासेतु

-6-लेन एक्स्ट्राडोसेड ब्रिज से सीमा कनेक्टिविटी होगी मजबूत

गुवाहाटी । असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा देश का सबसे लंबा भूकंपरोधी एक्स्ट्राडोसेड पुल अब लगभग तैयार हो चुका है। यह 6-लेन का आधुनिक 'महासेतु' उत्तरी और दक्षिणी गुवाहाटी को जोड़ेगा और पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को नई मजबूती देगा। करीब 99 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे। यह पुल कई मायनों में खास है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे भूकंप-रोधी तकनीक से डिजाइन किया गया है। असम का इलाका उच्च भूकंपीय जोन में आता है, जहां तेज झटकों की आशंका बनी रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुल में विशेष पेंडुलम सिस्टम लगाया गया है। यह सिस्टम भूकंप के दौरान आने वाले झटकों की ऊर्जा को सोखकर उन्हें नीचे की दिशा में ट्रांसफर कर देता है, जिससे पुल की संरचना सुरक्षित रहती है और नुकसान की संभावना कम होती है। इंजीनियरों के मुताबिक इस पुल की अनुमानित उम्र करीब 100 साल रखी गई है। यह देश का सबसे लंबा एक्स्ट्राडोसेड ब्रिज होगा। एक्स्ट्राडोसेड तकनीक गर्डर और केबल—दोनों सिस्टम का मेल होती है। इसमें केबल-स्टे ब्रिज जैसी केबल सपोर्ट मिलती है, लेकिन टावर अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। इससे लागत कम रहती है और मजबूती ज्यादा मिलती है। यह डिजाइन लंबी दूरी के पुलों के लिए काफी असरदार माना जाता है।

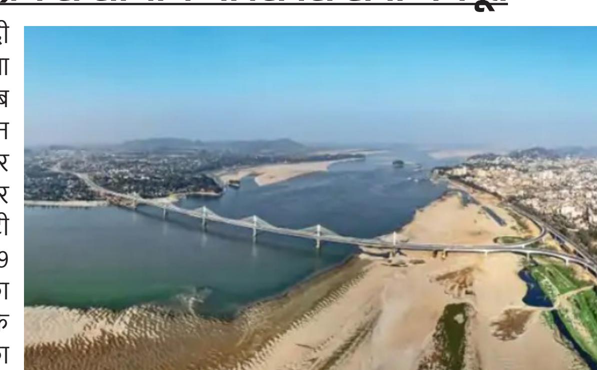

कम मेंटेनेंस, ज्यादा स्थिरता और बेहतर लोड क्षमता इसकी बड़ी खूबियां हैं। रणनीतिक नजरिए से भी यह पुल बेहद अहम है। इसके बन जाने से गुवाहाटी शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आवागमन तेज व आसान बनेगा। साथ ही चीन से सटे सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच और सप्लाई लाइन मजबूत होगी। रक्षा, आपदा प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से यह कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। पुल के निर्माण में आधुनिक मैटेरियल, हाई-स्ट्रेंथ कंक्रीट और एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें स्मार्ट सेंसर भी लगाए जा रहे हैं, जो भविष्य में स्ट्रक्चर की सेहत पर नजर रखेंगे। किसी भी तरह की दरार, कंपन या दबाव में बदलाव का डेटा तुरंत कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचेगा, जिससे समय रहते मरम्मत संभव होगी। स्थानीय लोगों और व्यापार जगत को भी इससे बड़ा फायदा मिलेगा।

गुयाना के मंत्री का हिंदी भाषण वायरल, संसद में विपक्ष को दी खुली बहस की चुनौती

जॉर्जटाउन (एजेंसी)। दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना की संसद में भारतीय मूल के मंत्री विकाश रामकिसून का हिंदी में दिया गया भाषण इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। उनका यह भाषण उस समय सामने आया जब विपक्ष के एक सांसद ने सदन में यह टिप्पणी कर दी कि रामकिसून को हिंदी का एक शब्द भी नहीं आता। इस टिप्पणी के जवाब में मंत्री ने स्पीकर से अनुमति ली और सीधे हिंदी में बोलना शुरू कर दिया। संसद में माहौल उस समय दिलचस्प हो गया जब रामकिसून ने बिना किसी कागज़ या नोट्स के धाराप्रवाह हिंदी में अपनी बात रखी। उन्होंने विपक्षी सांसद विष्णु पांडेय को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे किसी भी विषय पर, किसी भी मंच पर हिंदी में बहस करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "विषय आप चुन लीजिए, जगह आप तय कर लीजिए, मैं बिना कागज़ देखे हिंदी में बहस करूंगा।" उनके इस आत्मविश्वास भरे बयान के बाद सदन में काफी हलचल देखने को मिली। रामकिसून के भाषण का वीडियो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया, जिसे गुयाना स्थित भारतीय उच्चायोग ने पोस्ट किया। देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया। भारत समेत कई देशों के लोगों ने मंत्री की हिंदी बोलने की क्षमता और आत्मविश्वास की तारीफ की। कई यूज़र्स ने लिखा कि भाषा को लेकर सवाल उठाना बेवजह था और मंत्री ने अपने जवाब से सबको संतुष्ट कर दिया।

विकाश रामकिसून इस समय गुयाना के कृषि मंत्रालय में मंत्री हैं और पहले वे कृषि मंत्रालय के संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। भारतीय मूल के होने के कारण उनका हिंदी से जुड़ाव स्वाभाविक माना जा रहा है। उनका यह भाषण न सिर्फ राजनीतिक जवाब था, बल्कि भाषा और पहचान से जुड़ा एक मजबूत संदेश भी बन गया। दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के मंत्री विकाश रामकिसून का हिंदी में भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विपक्ष के सांसद ने उनकी हिंदी पर सवाल उठाया था, जिसके जवाब में रामकिसून ने बिना नोट्स के धाराप्रवाह हिंदी में बहस की चुनौती दी।

एपस्टीन विवाद से ब्रिटेन की सियासत गरम

-शबाना महमूद बन सकती हैं पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री

लंदन (एजेंसी)। ब्रिटेन की सियासत में इन दिनों हलचल तेज बताई जा रही है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर दबाव बढ़ने की खबरों के बीच लेबर पार्टी के अंदरूनी मतभेद भी सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े पुराने संपर्कों और नियुक्तियों को लेकर उठे विवाद ने सरकार की छवि पर असर डाला है। हालांकि स्टार्मर ने पद छोड़ने से इनकार किया है और कहा है कि वे अपना कार्यकाल जारी रखेंगे। इसी राजनीतिक माहौल में संभावित नए प्रधानमंत्री के नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, उनमें गृह मंत्री शबाना महमूद, स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग और वरिष्ठ नेता अंगेला रेनर शामिल हैं। इन नामों को लेकर पार्टी के भीतर अलग-अलग धड़ों में मंथन चल रहा है। शबाना महमूद का नाम खास तौर पर सुर्खियों में है। वे कश्मीरी मूल के परिवार से आती हैं और उनके परिवार की जड़ें PoK के मीरपुर क्षेत्र से जुड़ी बताई जाती हैं। वे पहले ही ब्रिटेन की राजनीति में एक अहम चेहरा बन चुकी हैं और गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम

महिला मानी जाती हैं। अगर भविष्य में वे प्रधानमंत्री बनती हैं, तो यह ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई मुस्लिम नेता इस पद पर पहुंचेगा। विवाद की एक कड़ी डाउनिंग स्ट्रीट के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैकस्वीनी के इस्तीफे से भी जुड़ी बताई जा रही है। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने पीटर मंडेलसन की एक महत्वपूर्ण राजनयिक पद पर नियुक्ति का समर्थन किया, जिस पर बाद में सवाल उठे। मैकस्वीनी ने इस फैसले को गलत मानते हुए पद छोड़ दिया। फिलहाल स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ब्रिटेन की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में नेतृत्व को लेकर तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। ब्रिटेन की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। प्रधानमंत्री स्टार्मर पर एपस्टीन विवाद के चलते दबाव है। संभावित नए पीएम में शबाना महमूद, वेस स्ट्रीटिंग और अंगेला रेनर के नाम चर्चा में हैं। शबाना महमूद पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं।

सीबीएसई 12वीं की कॉपियों की डिजिटल जांच:

-एक करोड़ उत्तरपुस्तिकाएं ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से होंगी चेक

नई दिल्ली। सीबीएसई (CBSE) ने 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के मूल्यांकन सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए इस बार कॉपियों की जांच डिजिटल तरीके से करने का फैसला किया है। बोर्ड के अनुसार करीब एक करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के लगभग 32 करोड़ पन्ने स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे और उनकी जांच ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) के जरिए होगी। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित होंगी और इस प्रक्रिया में 17 लाख से अधिक स्टूडेंट्स की कॉपियां शामिल होंगी। इस नई व्यवस्था के तहत परीक्षा पहले की तरह ऑफलाइन ही होगी। छात्र परीक्षा केंद्र पर कागज़ की कॉपी में ही अपने जवाब लिखेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि परीक्षा खत्म होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा केंद्र पर ही हाई सिक्योरिटी स्कैनिंग सिस्टम से स्कैन किया जाएगा। हर पन्ने की डिजिटल इमेज बनाकर उसे सुरक्षित सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद परीक्षक इन्हीं डिजिटल कॉपियों को स्क्रीन पर देखकर जांच करेंगे। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के मुताबिक इस डिजिटल सिस्टम से कॉपियों के ट्रांसपोर्ट में लगने वाला समय और खर्च बचेगा। पहले कॉपियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में काफी देरी होती थी और सुरक्षा का जोखिम भी रहता था। अब स्कैनिंग के तुरंत बाद कॉपियां सिस्टम में उपलब्ध होंगी, जिससे मूल्यांकन का काम तेज़ और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। इस

सिस्टम का एक बड़ा फायदा पारदर्शिता भी है। स्कैन की गई हर कॉपी को एक यूनिक कोड दिया जाएगा। कॉपी जांचते समय परीक्षक को छात्र का नाम, रोल नंबर या स्कूल की पहचान नहीं दिखाई देगी। इससे पक्षपात या पहचान के आधार पर नंबर देने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। मूल्यांकन पूरी तरह निष्पक्ष बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। पूरी प्रक्रिया को सात चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण: छात्र परीक्षा केंद्र पर पहले की तरह उत्तर पुस्तिका में जवाब लिखेंगे। अलग-अलग विषयों के लिए 40, 32 या 20 पेज की कॉपियां दी जाएंगी। परीक्षा प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है। दूसरा चरण: परीक्षा खत्म होने के बाद सभी उत्तर पुस्तिकाओं को स्कूल या केंद्र के कंप्यूटर लैब में ही हाई सिक्योरिटी स्कैनिंग सेंटर पर स्कैन किया जाएगा। हर पेज की साफ डिजिटल कॉपी बनाई जाएगी और सिस्टम पर अपलोड होगी। तीसरा चरण: मूल्यांकन के लिए नियुक्त शिक्षक अपने स्कूल में रहते हुए ओएसिस आईडी के जरिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद उन्हें बताया जाएगा कि उन्हें कितनी कॉपियां जांचनी हैं। चौथा चरण: शिक्षक के कंप्यूटर स्क्रीन पर छात्र की स्कैन की गई कॉपी खुलेगी। हर प्रश्न के सामने अलग मार्क्स कॉलम होगा। शिक्षक सवाल के जवाब के अनुसार नंबर भरेंगे और सिस्टम उसे तुरंत सेव कर लेगा। पांचवां चरण: पूरी कॉपी जांचने के बाद नंबर जोड़ने या कुल अंक निकालने की जरूरत नहीं होगी। टोटलिंग अपने आप सिस्टम करेगा, जिससे जोड़-घटाव की गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। छठा चरण: कुछ कॉपियों को मॉडरेशन या री-चेक के लिए वरिष्ठ परीक्षक के पास भी भेजा जा सकता है। सिस्टम में पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि किस शिक्षक ने कब और कितनी देर में मूल्यांकन किया। सातवां चरण: फाइनल नंबर सीधे सीबीएसई के रिजल्ट डेटाबेस में पहुंच जाएंगे। मार्क्स ट्रांसफर, मैनुअल एंट्री या दोबारा सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया तेज़ और विवाद-रहित होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह डिजिटल जांच व्यवस्था फिलहाल सिर्फ 12वीं बोर्ड के लिए लागू की गई है। 10वीं की कॉपियों की जांच पहले की तरह कागज़ पर ही होगी। बोर्ड का मानना है कि यह नया सिस्टम समय की बचत, खर्च में कमी, पारदर्शिता और सटीकता — चारों मामलों में फायदेमंद साबित होगा। छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए यह एक आधुनिक और भरोसेमंद कदम माना जा रहा है।

मुद्रक, प्रकाशक व स्वत्वाधिकारी आरपी न्यूज़ नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड के लिये श्रीराम ऑफसेट, 14, शॉपिंग सेंटर, ज़ोरावरसिंह गेट के बाहर, आमेर रोड, जयपुर से मुद्रित तथा रॉयल पत्रिका कार्यालय: 4312, मोहल्ला नायकान, नाहरवाड़ा, जगन्नाथ शाह का रास्ता, रामगंज, जयपुर से प्रकाशित। पीआरबी एक्ट के अनुसार खबरों के चयन के लिए उत्तरदायित्व संपादक मुन्ना खान मोबाइल नंबर 9772552446, 8058969180 ई-मेल: rpnewsnetworkpvt.ltd@gmail.com